वर्ष-8 अंक-12

दिसम्बर 2018 मूल्य रुपए 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

राहुल का दिखा दम

राष्ट्रीय अध्यक्ष
इंडियन नेशनल कांग्रेस

तीन राज्यों में शानदार जीत पर कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी जी को हार्दिक बधाई

पं. दयानंद शुक्ला

सुरेश पाण्डेय
राष्ट्रीय अध्यक्ष
ग्लोबल पीस एण्ड हारमोनी फाउण्डेशन
दिल्ली फ्रेंड्स फाउण्डेशन

लोक जागृति संस्था की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

सुरेश पाण्डेय
राष्ट्रीय अध्यक्ष
ग्लोबल पीस एण्ड हारमोनी फाउण्डेशन
दिल्ली फ्रेंड्स फाउण्डेशन

2019

S.K. MISHRA
Advocate (Chief Editor
LOK JAGRITI PATRIKA)
Mob-9560522777, 9810960818

Add.: IIIA/95 Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010
B.O. E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi-110092
mail : cs.santosh@yahoo.com Website www.legeazy.com
lokjagriti@gmail.com, www.lokjagriti.com

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10– सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11– लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12– बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13– हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14– भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15– समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16– देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17– सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18– कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19– गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20– टोल टैक्स समाप्त करना।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं।लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं ।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारण से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.com

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010
lokjagriti@gmail.com, 9560522777

www.lokjagriti.com

कांग्रेस वापसी की ओर एक कदम

मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लोगों का अभिवादन करते (बाएं)। दूसरी ओर राजस्थान में सीएम पद की शपथ लेते अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते सचिन पायलट(बीच में)। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते भूपेश बघेल (दाएं)।

भोपाल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर कांग्रेस के दिग्गज नेता।

लोक जागृति पत्रिका

दिसम्बर 2018 वर्ष 8 अंक 12

संरक्षक

पं. दयानंद शुक्ला

कपिल सिंघल

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल, सुरेश पाण्डेय

समाचार संपादक

आलोक सोलंकी

बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी

आदेश नागर

विजय बहादुर सिंह

तेज सिंह यादव (एडवोकेट)

नरेन्द्र कुमार सक्सेना

गिरीश त्रिपाठी

एस.बी.एस. गौतम

सत्येंद्र श्रीवास्तव

अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)

राजेश कुमार मिश्र

तरुण गुप्ता (एडवोकेट)

पूनम सिंह (एडवोकेट)

शोभा चौधरी

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

धीरज पाण्डेय

प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

संजय मिश्रा

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा

साज सज्जा

A.N.R. Creation

7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक

संतोष कुमार मिश्रा

द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

अभी हाल में हुए चुनाव से ऐसा लगता है कि देश की जनता भ्रम जाल में फंसी हुई है उसी तरह से जैसे किसी को शरीर में दर्द है तो रात में नींद ना आने पर वह करवटें बदलता रहता है शायद नींद आ जाए दर्द से राहत मिल जाए लेकिन करवट बदलने से दर्द खत्म नहीं होता उसी तरह देश की जनता अपना मत देकर बार बार सरकार बदल रही है लेकिन उसको कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही सत्ता में लोग जनता की सेवा करने के नाम पर आते हैं लेकिन सत्ता पा जाने के बाद स्वयं मेवा खाने लग जाते हैं और सत्ता के मद्य में मस्त हो जाते हैं जनता की आवाज उन तक पहुंचती ही नहीं हमारे शासक सत्ता पा जाने के बाद सिर्फ जुमलेबाजी भाषण बाजी आपस में लड़ाई करा कर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। देश में भयंकर बेरोजगारी किसानों की बुरी हालत अस्पतालों स्कूल में खुली लूट, पुलिस द्वारा लोगों का शोषण अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है शासन–प्रशासन जनता की सुनने वाला है नहीं। चारों तरफ लूट मची हुई लेकिन जनता जनार्दन की समस्याओं से शासन प्रशासन को कोई लेना देना नहीं अब कुछ लोग कहेंगे की पहले भी ऐसा होता रहा है बिल्कुल सही है पहले भी ऐसा होता रहा है, तभी तो जनता ने उसको हटाकर नई सरकार को अपना भरपूर समर्थन दिया लेकिन यह सरकार भी लोगों को फायदा नहीं दे सकी इस वजह से जनता में भयंकर असंतोष फैला हुआ है, नोट बंदी जीएसटी और ऐसे काम सरकार द्वारा किए गए जो कि आम जनता को काफी परेशान करने वाले हैं जो बिना किसी सूझबूझ के और बिना प्लानिंग के किए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को सड़क पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है सीबीआई में खुलेआम भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा भी हुआ है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर भी उंगलियां उठ रही है ऐसे समय में जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा है 2014 में जिस तरह से लोग कांग्रेस के विरोध में थे जब मोदी जी आए थे तो लोगों में आशा की उम्मीद जगी थी लेकिन लोगों की उम्मीदें कम होती जा रही हैं सरकार सभी लोगों को बेईमान समझ के नीतियां बना रही है देश में कुछ बेईमान होते हैं कुछ ईमानदार भी होते हैं सरकार का यह काम है कि अपनी प्रशासनिक क्षमता के आधार पर बेईमानों को दंडित किया जाए ईमानदार को प्रोत्साहित किया जाए लेकिन सरकार सभी को एक ही डंडे से हाकना चाहती है इस वजह से चारों तरफ भय एवं अराजकता का माहौल बना हुआ है सरकार के लोग स्वयं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं . गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से अभी बुलंदशहर में बवाल हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है एक पुलिस अधिकारी की जिस तरह हत्या की गई और उसके बाद उसको राजनीतिक रंग दे कर के मामले को उलझा दिया गया है . गौ रक्षा की जगह गौ पालन करना चाहिए गौ रक्षकों को चाहिए कि वह गौ को पालना चालू कर दें . गौ पालन के साथ साथ मानव कल्याण ज्यादा जरूरी है. जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है उस देश में गौ पालन एक बेमानी हो जाती है सबसे पहले हमें किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए प्रयास करने जरूरी हैं किसान की आत्महत्या बंद हो जाएगी तभी सही मायने में गौरक्षा हो पाएगी गायों को पालने का काम ज्यादातर किसानों द्वारा किया जाता है , दिल्ली के लुटियन जोन में गौ रक्षा के सिर्फ नारे लगाए जा सकते हैं गाय पाली नहीं जा सकती इसीलिए मुद्दे को भटका करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं लेकिन गौ माता का फायदा नहीं किया जा सकता उनकी रक्षा नहीं हो सकती . हमारे सभी राजनीतिक दल देश की जनता के साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। सरकार में अगर कोई काम करता है तो पब्लिक उसकी सराहना करती है जैसे कि नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है साथ में दिल्ली की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं इस तरह से हमारे राजनीतिज्ञों को कुछ उदाहरण पेश करना चाहिए जिसे लोग मानने के लिए मजबूर हो अपने मुंह मिट्ठू बनना छोड़ के काम को करके दिखाना चाहिए।

कानून गरीबों को पीसते हैं, और अमीर लोग कानून पर शासन करते हैं।

2019 में भी हराएंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादाख़िलाफ़ी से नाराज़ होकर वोट दिया है।

पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों में विफल रही है और जनता ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है।

कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की तरफ़ बढ़ रही है।

राहुल ने कहा, "2014 के चुनावों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। 2014 का चुनाव मेरे लिए बेस्ट रहा। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा मौका गँवा दिया है। वे लोगों की दिल की बात सुनने में नाकाम रहे हैं।"

हम किसी को देश से हटाना नहीं चाहते, हमारी लड़ाई बीजेपी की विचाराधारा से है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज़गार का वादा पूरा नहीं किया है। लोगों को ये लगना लगा है कि मोदी ने जो भी वादे किए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं जहाँ भी प्रचार के लिए गया, मैंने ये महसूस किया है।

देश के लोग नोटबंदी, जीएसटी, बेरोज़गारी से खुश नहीं हैं। मैं बार–बार कहता हूँ नोटबंदी एक बड़ा घोटाला है।

तेलंगाना में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है। अहम मुद्दे रोज़गार, भ्रष्टाचार और किसानों के हैं, हम इन्हीं को सामने रखकर लड़े हैं।

विपक्ष बेहद मजबूत है और मोदी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे।

अगर मध्य प्रदेश में सपा–बसपा का साथ लेना पड़ा तो लेंगे। एसपी–बीएसपी और कांग्रेस की विचाराधारा एक है। उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा।

ईवीएम का सवाल सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, बल्कि दुनियाभर में ये सवाल उठा है।(एजेंसी)

मोदी ने सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिखाया कि 'क्या नहीं करना चाहिए' और उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार से भी 'काफी कुछ सीखा।' राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को विशाल जनादेश मिला था, लेकिन उन्होंने 'देश की धड़कन' सुनने से इनकार कर दिया। हिंदीभाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फिर से उदय के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, 'मैं कल अपनी मां से बात कर रहा था और मैं उनसे कह रहा था कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात कुछ हुई है तो वह है 2014 का (लोकसभा) चुनाव। मैंने उस चुनाव से काफी कुछ सीखा है।' राहुल (48) ने कहा कि 2014 के चुनाव से उन्हें जो सबसे अहम चीज सीखने को मिली, वह 'विनम्रता' है। उन्होंने कहा, 'यह एक महान देश है और इस देश में सबसे अहम चीज है कि लोग क्या मानते हैं।' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक नेता के तौर पर यह समझना होता है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं और वह जिस चीज को महसूस करते हैं, उससे जुड़ाव पैदा करना होता है। उन्होंने कहा, 'बेबाकी से कहूं तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सबक सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए।' राहुल ने कहा कि पांच साल पहले उन्हें (मोदी को) इस देश में बदलाव लाने का बड़ा मौका दिया गया।(एजेंसी)

ज्ञान का मूल्य बहुमूल्य रत्न से भी अधिक है।

राहुल गांधी ने क्या वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी?

2019 के आम चुनाव से ठीक पहले पाँच राज्यों के चुनावी परिणाम को फ़ाइनल से पहले का सेमीफ़ाइनल माना जा रहा था। इस सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले में कांग्रेस ने ये दिखाया है कि वो बीजेपी को ना केवल उसके गढ़ में चुनौती दे सकती है, बल्कि उसे सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है।

सबसे पहली बात तो यही है कि इन नतीजों ने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुक़ाबले में खड़ा कर दिया है। राहुल ये साबित करने में कामयाब रहे हैं कि वे नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, उनसे मुक़ाबला कर सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं।

एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं "ज़ाहिर है कि इन नतीजों से राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस मज़बूत होगा और 2019 में वे कहीं ज़्यादा तैयारी से चुनाव मैदान में जाएंगे।"

राहुल की इस जीत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 सालों से चली आ रही बीजेपी सरकार के इन्कंबेंसी फैक्टर का भी योगदान रहा है, यही बात राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी के तौर पर कही जा सकती है.

लेकिन इन चुनावों में राहुल गांधी ने खुद के नेता के तौर पर भी विकसित किया है।

बीबीसी हिंदी के साथ फ़ेसबुक लाइव में वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने कहा, "मध्य प्रदेश में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि अंदरूनी होड़ ज़रूर थी लेकिन राहुल गांधी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे।"

इतना ही नहीं राहुल गांधी ने राजस्थान में भी ये सुनिश्चित किया कि बाहर से जाकर सचिन पायलट संगठन का काम कर सकें और बाद में अशोक गहलोत जैसा अनुभवी नेता राज्य में पहुंचकर चुनावी अभियान को मज़बूत करे, हालांकि इन दोनों के बीच भी टिकट बंटवारे को लेकर आपसी गुटबाजी की ख़बरें आती रहीं लेकिन दोनों एक साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाते रहे।

छत्तीसगढ़ में इस तरह से अपने नेताओं की आपसी खींचतान का सामना राहुल गांधी को नहीं करना पड़ा, लेकिन वहां पार्टी के पास कोई दमदार चेहरा भी नहीं था। ऐसे में ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने राहुल गांधी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट डाला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 90 में 60 से ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है, इस राज्य में राहुल गांधी ने पांच दौरे करके करीब 18 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध बताते हैं, "राहुल गांधी की सभाओं में यहां भीड़ उमड़ रही थी, ख़ासकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे और घोषणा पत्र के तमाम वादे समय–सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे।"कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तुलना में करीब 10 फ़ीसदी ज़्यादा वोट मिले हैं। तीन राज्यों में सबसे ज़ोरदार जीत कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में ही मिली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर भले मिली हो लेकिन राहुल गांधी के लिए भरोसा बढ़ाने वाली बात ये है कि ये दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत के लिहाज से बेहद मज़बूत राज्य रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस का यहां जीत हासिल करने से कांग्रेस के लिए मोराल बूस्टर साबित होने वाला है। ये भी दिलचस्प संयोग है कि ये नतीजा राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक एक साल बाद आया है। लोकसभा चुनाव से महज़ चार महीने पहले उन राज्यों में जहां से बीजेपी को अधिकतम सीटें हासिल हुई थीं, उन राज्यों में सरकार हासिल करके राहुल गांधी ने 2019 के मुक़ाबले का टोन सेट कर दिया है।

पहले पंजाब, फिर गुजरात और कर्नाटक, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चुनाव कमान संभालने के साथ राहुल गांधी समय के साथ राजनीतिक तौर पर मैच्योर होते भी नज़र आ रहे हैं।

झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात् मृत्यु के समान है।

अहंकार को एक दिन टूटना ही होता है

अहंकार को एक दिन टूटना ही होता है। अहंकार की नियति ही टूटना है। इतिहास गवाह है कि किसी का भी अहंकार कभी ज़्यादा वक़्त तक नहीं रहा। इस अहंकार की वजह से बड़ी–बड़ी सल्तनतें नेस्तनाबूद हो गईं। किसी हुकूमत को बदलते हुए वक़्त नहीं लगता। बस देर होती है अवाम के जागने की। जिस दिन अवाम बेदार हो जाती है, जाग जाती है, उसी दिन से हुक्मरानों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही तो हुआ। यहां अहंकार हार गया और विनम्रता जीत गई। चुनाव नतीजों वाले दिन शाम को हुई प्रेस कान्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनसे मैंने यह सीखा कि एक पॉलिटिशियन होने के नाते मुझे क्या नहीं कहना या करना चाहिए।

ये राहुल गांधी का धैर्य, विनम्रता और शालीनता ही है कि उन्होंने विपरीत हालात का हिम्मत से मुक़ाबला किया। जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए, चुनावों में नाकामी मिलने पर उनका मज़ाक़ उड़ाया गया, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने कभी अपनी तहज़ीब नहीं छोड़ी, अपने संस्कार नहीं छोड़े। उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मिज़ोरम और तेलंगाना में जीतने वाले दलों को मुबारकबाद दी। चुनावों में जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं। अहंकार कभी उन पर हावी नहीं हुआ। विधानसभा चुनावों में जीत का श्रेय उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी में हार को क़ुबूल करने की हिम्मत भी है। पिछले चुनावों में नाकामी मिलने पर उन्होंने हार का ज़िम्मा खुद लिया। ये सब बातें ही तो हैं, जो उन्हें महान बनाती हैं और ये साबित करती हैं कि उनमें एक महान नेता के सभी गुण मौजूद हैं।

अमूमन देखा जाता है कि जब कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो उसे घमंड हो जाता है। राजनेता बेलगाम हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सत्ता उनकी मुट्ठी में है, वे जो चाहें कर सकते हैं। उन्हें टोकने, रोकने वाला कोई नहीं है। साल 2014 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बड़े–बड़े वादे किए थे। उन्हें खूब सब्ज़ बाग़ दिखाए थे, लेकिन सत्ता में आते ही अपने वादों से उलट काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन उसके शासनकाल में महंगाई आसमान छूने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन आए–दिन महिला शोषण के दिल दहला देने वाले मामले सामने आने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को राहत देने का वादा किया था, लेकिन किसानों के खुदकुशी के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। किसानों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन रोज़गार देना तो दूर, नोटबंदी और जीएसटी लागू करके जो उद्योग–धंधे चल रहे थे, उन्हें भी बंद करने का काम किया है। जो लोग काम कर रहे थे, वे भी रोज़ी–रोटी के लिए तरसने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी फ़ैसले ले रही है, उनसे सिर्फ़ बड़े उद्योग. पतियों को ही फ़ायदा हो रहा है। ऑक्सफ़ेम सर्वेक्षण के मुताबिक़ पिछले साल यानी 2017 में भारत में सृजित कुल संपदा का 73 फ़ीसद हिस्सा देश की एक फ़ीसद अमीर आबादी के पास है। राहुल गांधी ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सवाल भी किया था। ग़ौरतलब है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं और उनकी सरकार पर अमीरों के लिए काम करने और उनके कर्ज़ माफ़ करने को लेकर लगातार हमला करते रहे हैं। इतना ही नहीं भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुए राफ़ेल लड़ाकू विमान सौदे पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

दरअसल, एक तरफ़ केन्द्र की मोदी सरकार अमीरों को तमाम सुविधाएं दे रही है, उन्हें करों में छूट दे रही है, उनके कर माफ़ कर रही है, उनके क़र्ज़ माफ़ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ़ ग़रीब जनता पर आए दिन नये–नये कर लगाए जा रहे हैं, कभी स्वच्छता के नाम पर, तो कभी जीएसटी के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है। खाद्यान्नों और रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ों के दाम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मरीज़ों के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। दवाओं यहां तक कि जीवन रक्षक दवाओं और खून के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में ग़रीब मरीज़ कैसे अपना इलाज कराएंगे, इसकी सरकार को ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। सरकार का सारा ध्यान जनता से कर वसूली पर ही लगा हुआ है। वैसे भी प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि उनके खून में व्यापार है। (साभार : इंटरनेट)

वही सबसे तेज चलता है, जो अकेला चलता है।

राहुल और मोदी के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों के क्या मायने है?

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में निराशा है।

हालांकि मध्य प्रदेश में कड़ा मुक़ाबला रहा और कांग्रेस बहुमत से कुछ दूर रह गई, लेकिन निर्दलीय, बसपा और सपा के समर्थन के बाद वहाँ भी सरकार बनाने का रास्ता साफ़ हो गया है।

इन विधानसभा चुनाव के नतीजे राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ–साथ नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए क्या मायने रखते हैं?

बीजेपी के लिए इन नतीजों का मतलब

"नरेंद्र मोदी आज भी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन जब उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी तो बीजेपी का कुल वोट शेयर 31 फीसदी था। अब साढ़े चार साल बाद उनकी लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। ज़मीन पर लोग सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ।"

"2013 से 2017 तक भारतीय राजनीति में मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं था। लेकिन आज उनसे ये ख़िताब छिन गया है। चुनाव जिताऊ नेता वाली उनकी छवि को धक्का लगा है। ये तो साफ है कि लोगों का मोदी से मोहभंग हो रहा है लेकिन आगामी संसदीय चुनाव में मतदान पर इसका क्या असर पड़ेगा ये तो वक़्त ही बताएगा।"

इन चुनावी नतीजों से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अब बीजेपी में मोदी विरोध के स्वर उभरना शुरू होंगे। इस सवाल पर संजय श्रीवास्तव ने कहा, "बीजेपी में मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ें अभी उठना शुरू नहीं होंगी। लेकिन बीजेपी में एक धड़ा ऐसा भी है जो कि उस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी–शाह की जोड़ी 170 लोकसभा सीटों पर सिमट जाती है तो मोदी जी सहयोगी दलों को कैसे जुटा पाएंगे। लेकिन ये भी संभव है कि मोदी और अमित शाह में चुनावी गणित के चक्कर में थोड़ी विनम्रता आ जाए।"

राहुल गांधी ने बीते साल 11 दिसंबर, 2017 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी।

इसके ठीक एक साल बाद आए चुनावी नतीजों ने बता दिया है कि राहुल गांधी परिपक्वता से फैसले लेने के लिए सक्षम हैं।

"लेकिन कई विपक्षी दलों ने अभी तक राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कई दलों के नेता निजी बातचीतों में बताते हैं कि राहुल गांधी व्यक्ति तो बेहतरीन हैं लेकिन उनके अंदर वोट हासिल करने की क्षमता नहीं है।"

ऐसे में सवाल उठता है कि इन विधानसभा चुनावों के नतीजों के राहुल गांधी के लिए क्या मायने हैं।

वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने पांच में से तीन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी बढ़ जाएगा। चुनावी रणनीति की बात करें तो राहुल गांधी ने इन चुनावों में दो तरह की रणनीति को अपनाया है।"

"राहुल की रणनीति में एक चीज साफ़ दिखाई दी है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने बसपा, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दलों के साथ समझौता नहीं किया जिससे सपा–बसपा काफ़ी नाराज़ हैं।"

"कांग्रेस ने ये सोचा कि ये राज्य कभी उसके गढ़ हुआ करते थे। ऐसे में एक शक्ति परीक्षण करना चाहिए। कांग्रेस की इस रणनीति का एक पहलू ये भी है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में टीडीपी और एक अन्य दल के साथ गठबंधन किया। इस तरह कांग्रेस ने अलग–अलग चुनावी रणनीतियों का इस्तेमाल किया।"

गुजरात के चुनाव से लेकर इन चुनावों में भी राहुल गांधी मंदिर–मंदिर जाने के साथ–साथ उन्होंने अपना गोत्र भी बताया।

स्मिता गुप्ता राहुल की इस रणनीति पर बताती हैं, "कांग्रेस ने हिंदी भाषी प्रदेशों में विचारधारा के तौर पर एक नया प्रयोग किया है। 90 के दशक से देश की राजनीति में दक्षिणपंथ प्रवेश कर रहा था (साभार : पीएस)

प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असम्भव नजर आता है।

राहुल गांधी क्या अब 'ब्रांड राहुल' बन पाएंगे?

तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेस करने की आई, तो मीडिया वालों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा।

वैसे तो हर जीत–हार के बाद दोनों पार्टी के अध्यक्षों के लिए ये एक रस्म–अदाएगी जैसी होती है, जहां पार्टी

अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इस प्रेस कांफ्रेस को केवल एक प्रेस कांफ्रेस की तरह नहीं लिया।

राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड में प्रेस कांफ्रेस की शुरुआत कार्यकर्ताओं और वोट देने वालों को धन्यवाद देते हुए ही की थी, लेकिन वो सवालों से बचकर वापस जाने की जल्दबाज़ी में नहीं दिखे।

राहुल गांधी अलग ही तेवर और अंदाज़ में दिखे। मानों तीन राज्यों की जीत ने कांग्रेस से ज़्यादा उत्साह उन में भर दिया हो।

कांग्रेस अध्यक्ष के इस नए तेवर की चर्चा प्रेस कांफ्रेस ख़त्म होते ही टीवी स्डूडियो के साथ–साथ पार्टी दफ़्तर और सोशल मीडिया में भी छाई रही।

पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल से एक सवाल पूछा गया, बीजेपी हमेशा 'कांग्रेस मुक्त भारत' की बात करती है, क्या कांग्रेस की वापसी के बाद 'बीजेपी मुक्त भारत' की शुरूआत होगी?

राहुल ने बड़े ही सधे अंदाज़ में जवाब दिया, "हमारी अप्रोच अलग है। बीजेपी की एक विचारधारा है। हम उस विचारधारा के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है। उनको हम 2019 में हराएंगे। मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। अगर लोगों की सोच हमसे अलग है तो हम उस सोच से लड़ेंगे, हम उन्हें देश से मिटाना नहीं चाहते।" "राहुल गांधी के इस जवाब में उनकी सबको साथ लेकर चलने की सोच और विचारधार साफ़ झलकती है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये बात राहुल गांधी समझते हैं और यही उनके जवाब में दिख रहा है। यही उनको ब्रांड मोदी से अलग करता है।" एक ही तरह के दो ब्रांड बाज़ार में एक–दूसरे से तभी प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं, जब दोनों में बुनियादी फ़र्क़ हो। साल 2019 के लिहाज़ से देखें तो भारतीय राजनीति में दो अलग, बुनियादी फ़र्क़ वाले ब्रांड साफ़ देखने को अब मिल रहे हैं। कोई ब्रांड तब बनता है जब वो जनता की नब्ज़ पकड़ ले। इस बार राहुल ऐसा करने में थोड़े कामयाब हुए। राफ़ेल की बात उन्होंने की जिससे लोगों ने ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया, लेकिन किसानों की बात करके उन्होंने किसानों के बीच अपनी पहचान ज़रूर बना ली। पिछले कुछ वर्षों में यही उनकी उपलब्धि रही है। हालांकि मोदी की तरह उन्होंने अभी भी जुमलेबाज़ी नहीं सीखी है, पर वो बेहतर ज़रूर हुए हैं। इस जीत ने पार्टी के भीतर, नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता बढ़ा दी है। "राहुल गांधी में राजनीति के शुरूआती अमृत मंथन के बाद एक ठहराव आया है। जैसे अमृत मंथन के बाद अमृत और विष का अंतर साफ़ हुआ था, राहुल ने भी अच्छी बातों को अपने में समाहित किया है और बुरी बातों से तौबा कर लिया है। ये जीत उनके लिए संजीवनी का काम करेगी।"

कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल गांधी से अलग 'ब्रांड राहुल' बनकर तभी उभरेंगे, जब उनमें 'ब्रांड मोदी' से अलग कोई बात हो। वो कहते हैं, "मोदी 'सबका साथ सबका विकास' का नारा तो देते हैं लेकिन पार्टी में सब जानते हैं कि विकास किसका हो रहा है। लेकिन राहुल ने इन चुनावों में ये साफ़ दिखा दिया कि युवा–जोश, जातिगत–समीकरण और पार्टी के अनुभवी नेताओं को साथ लेकर कैसे चला जा सकता है।" राहुल अपनी 'पप्पू वाली छवि' से अब निकल गए हैं। ''अब ग्राउंड पर उन्हें कोई पप्पू नहीं कहता। लोग उन्हें अब 'सीरियस प्लेयर' मानने लगे हैं। ब्रांड राहुल के तौर पर ये उनकी बहुत बड़ी जीत है।'' ''हार को गरिमा के साथ हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन जीत को गरिमा के साथ कैसे स्वीकार किया जाता है, वो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कांफ्रेस के साथ दिखाया। उनके अंदाज़ में एक ठहराव था, समग्रता की बात थी, अकड़ नहीं थी और परिपक्वता साफ़ झलक रही थी। (साभार : पीएस)

एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नीव बना सके।

अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम, सचिन पायलट डिप्टी सीएम

राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हुए लंबे मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गतिरोध खत्म करते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री नामित किया। गांधी के आवास पर दो दिनों तक कई दौर की बैठकों के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर सहमति बनी जिसे पार्टी ने 'अनुभवी और ऊर्जावान नेतृत्व' का मेल करार दिया है। राजस्थान के लिए पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला किया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। इसके साथ सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे।'' उन्होंने कहा, ''अनुभवी और ऊर्जावान नेतृत्व एक साथ आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष इसमें विश्वास करते हैं। यह नेतृत्व पार्टी को मजबूत करेगा और राजस्थान के लोगों की अकांक्षाओं को पूरा करेगे।''

गहलोत ने कहा, ''मैं अपने नेता राहुल गांधी जी और नवनिर्वाचित विधायकों का आभारी हूं कि उन्होंने यह फैसला किया। मुझे एक बार फिर राजस्थान का सेवा करने का अवसर मिलेगा।'' उन्होंने कहा, ''चुनाव प्रचार के दौरान हमने कई मुद्दे उठाए। हमने और राहुल गांधी जी ने सुशासन की बात है। इस मुबारक मौके पर मैं यह कह सकता हूं कि मैं और सचिन पायलट जी मिलकर राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप काम करेंगे।''

पायलट ने कहा, ''किसको मालूम था कि दो–दो करोड़पति बन जाएगें। मैं राहुल गांधी जी और विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं गहलोत जी की बधाई देता हूं।'' उन्होंने कहा, ''तीनों राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के चुनाव देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। ये देश को संतोष देने वाले थे। जो लोग आशा खो चुके थे उनको आशा देने वाले हैं।'' पायलट ने भरोसा जताया कि कांग्रेस का अच्छा चुनावी प्रदर्शन जारी रहेगा और पार्टी को 2019 चुनावों में बड़ा जनादेश मिलेगा और वह सरकार बनाएगी।

वेणुगोपाल ने कहा, ''हम आज राज्यपाल से मिलेंगे और शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम पर फैसला लेंगे।'' कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर कई दौर की बैठकों के बाद सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने फिर से बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर सहमित बनी। (एजेंसी)

खरी-खरी

लोक कल्याण की योजना के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा

मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है।

कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने कुछ कर दिखाया तो भाजपा की राह मुश्किल होगी

सुरेश पांडेय

पांच राज्यों में हुए चुनावों के नतीजों के कारण भाजपा का मनोबल पातालगामी हो रहा है और कांग्रेस का गगनचुंबी ! लेकिन थोड़ी गहराई में उतरें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों मनस्थितियां अतिवादी हैं। सच्चाई कहीं बीच में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस, दोनों को जनता ने अधर में लटका दिया। दोनों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को सीटें थोड़ी ज्यादा मिलीं लेकिन वोटों का हाल क्या रहा। मध्य प्रदेश में तो भाजपा को कांग्रेस से भी ज्यादा वोट मिले। उसके उम्मीदवारों को यदि कुछ सौ वोट और मिल जाते तो सरकार भाजपा की ही बनती। इस चुनाव में मुख्यमंत्री शिव. राज चौहान की कुर्सी तो चली गई लेकिन इज्जत बच गई। बल्कि बढ़ गई।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी कहा जा सकता है कि 'खूब लड़ी मर्दानी'। इसी प्रकार राजस्थान में कांग्रेस को भाजपा से जो ज्यादा वोट मिले, वे भी एक प्रतिशत से कम ही थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इन दोनों बड़े प्रदेशों में ये दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर ही छूटीं। छत्तीसगढ़ की बात अलग है। वहां भाजपा के वोट भी काफी कम हुए है और सीटों का तो भट्ठा ही बैठ गया। लेकिन जरा सोचें कि यदि भाजपा अपना प्रधानमंत्री बदल ले या अगले पांच–छह महिने में दो–तीन चमत्कारी काम कर दे तो कांग्रेस क्या करेगी ?

कोई जरुरी नहीं है कि लोग कांग्रेस को उतने ही वोट दें, जितने कि उन्होंने अभी दिए हैं। और फिर अखिल भारतीय स्तर पर आज भी भाजपा कांग्रेस से काफी आगे है। मिजोरम और तेलंगाना में कांग्रेस का हाल क्या हुआ है ? ये बात दूसरी है कि राहुल गांधी की छवि सुधरी है। अब राहुल को 'पप्पू' कहना जरा मुश्किल होगा, हालांकि गप्पूजी ने खुद को उलटाने का पूरा प्रबंध कर रखा है। इस प्रबंध का पहला झटका अभी तीना. हिंदी प्रदेशों ने दिया है। पप्पूजी को अपने आप श्रेय मिल रहा है। पप्पूजी ने गप्पूजी को पहले संसद में झप्पी मारी थी, अब सड़क पर मार दी है। साढ़े चार साल गप्प मारते–मारते गप्पूजी ने निकाल दिए। अब वे पांच–छह माह में कौन–सा बरगद उखाड़ लेंगे, समझ में नहीं आता। इश्के–बुतां में जिंदगी गुजर गई मोमिन। अब आखरी वक्त क्या खाक मुसलमां होंगे ?

यह असंभव नहीं कि इन तीनों हिंदी प्रदेशों के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अगले चार–छह महिने में कुछ ऐसे विलक्षण काम कर दिखाएं जो 2019 के चुनावों में छा जाएं। यदि ऐसा हो जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। 2019 में केंद्र में जो भी सरकार बनेगी, उसके लिए पहले से एक नक्शा तैयार रहेगा। वरना, भारत की जनता को फिर अगले पांच–साल रोते–गाते गुजारने होंगे।

खरी-खरी

स्वच्छ भारत का मात्र प्रचार किया जा रहा है

जीत की खुशी में हार भूल गई कांग्रेस

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को मिली जीत इतनी बड़ी है कि अन्य लोगों की तो छोड़ दीजिये कांग्रेस का भी ध्यान शायद इस बात की ओर नहीं गया कि इन दो राज्यों में पार्टी की करारी हार हुई है। मिजोरम में तो कांग्रेस लगातार दो बार से सत्ता में थी वहां पार्टी की ना सिर्फ करारी हार हुई है बल्कि यह हार कई मायनों में ऐतिहा. सिक भी है। मिजोरम में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करते रहे मुख्यमंत्री ललथनहावला जोकि 2013 में हुए विधानसभा चुनावों में लगातार 9वीं बार विधायक चुने गये थे और एक साथ दो सीटों से विधायक बने थे, वह ललथनहावला इस बार दोनों सीटों पर अपना चुनाव खुद हार गये। मिजोरम में कांग्रेस की हार के बड़े कारणों में दस साल की सत्ता विरोधी लहर के अलावा कांग्रेस सरकार की मद्य नीति भी है। जनता ने शायद उदार मद्य नीति की वजह से ललथनहवला को नकार दिया। यही नहीं मिजोरम की सत्ता गँवाते ही कांग्रेस भारत के उत्तर–पूर्व भूभाग से पूरी तरह साफ हो गयी है क्योंकि इस क्षेत्र का यही एकमात्र राज्य था जहाँ कांग्रेस की सरकार बची हुई थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा का सूपड़ा साफ होने की बात कहने वालों की नजर जरा मिजा. रम पर भी जानी चाहिए जहां 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास पिछली बार 34 सीटें थीं वहीं अब वह मात्र 5 पर सिमट गयी है। जो विश्लेषक कांग्रेस की मिजोरम में करारी हार को गंभीरता से नहीं ले रहे उन्हें यह पता होना चाहिए कि उत्तर–पूर्व में लोकसभा की 21 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर पार्टी एक तरह से कमजोर हो गयी है।

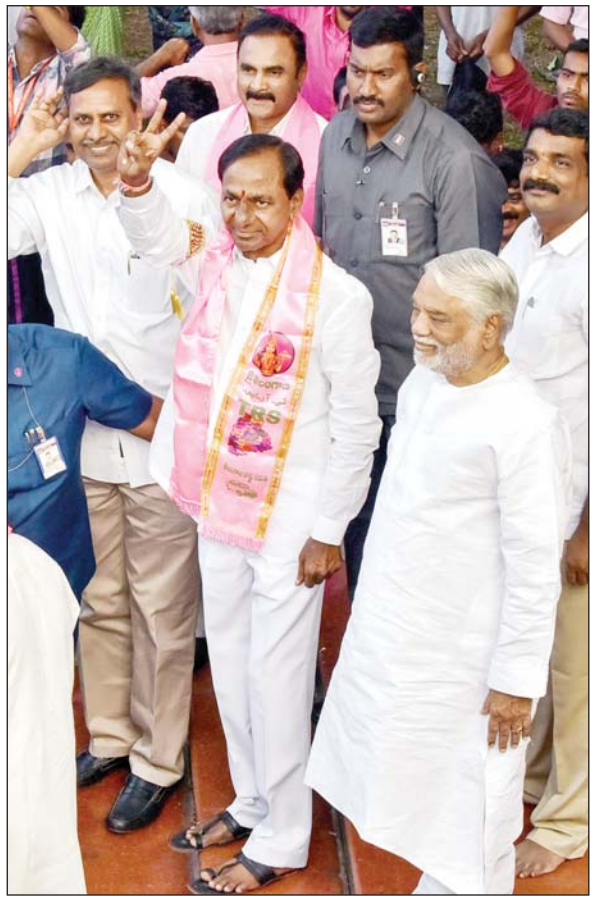

2019 में कांग्रेस का काम सिर्फ पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से नहीं चलेगा बल्कि उसे देश के हर भूभाग में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि अभी जो राजनीतिक हालात हैं, कांग्रेस सिर्फ उन्हीं राज्यों में मजबूत है जहां भाजपा से उसका सीधा मुकाबला है। जिन–जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हावी हैं वहां कांग्रेस की हालत पतली है और उसे सहयोगियों की बैसाखी की सख्त जरूरत है। ऐसे राज्यों में जम्मू–कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, केरल और उत्तर–पूर्व के राज्य शामिल हैं।

इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ा निर्णय करते हुए आंध्र प्रदेश में अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी तेलुगू देशम पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था लेकिन कुछ काम नहीं आया। तेलंगाना में तो संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी तक ने पार्टी के लिए रैली की थी जबकि वह अन्य चार राज्यों में एक भी रैली को संबोधित करने नहीं गईं। यही नहीं राहुल गांधी और तेदेपा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने एक मंच से चुनावी सभा को संबोधित किया लेकिन केसीआर के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की लहर में यह गठबंधन कहीं टिक नहीं पाया। कांग्रेस जहाँ उत्तर भारत में हिंद. वादी राजनीति कर रही थी वहीं तेलंगाना में तो उसने अपने घोषणापत्र में मुस्लिमों के लिए अलग से जो सहुलियतें देने की घोषणा की थी उससे उसका तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला चेहरा ही उजागर हुआ था। लेकिन यह सब कुछ काम नहीं आया और कांग्रेस को 28.4 प्रतिशत मतों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस का कमजोर संगठन भी यहां पार्टी की हार के कारणों में प्रमुख रहा।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का तेलंगाना में तेदेपा के साथ गठबंधन का फैसला कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ क्योंकि इससे तेलंगाना की जनता में गलत संदेश गया। दरअसल तेदेपा अलग तेलंगाना राज्य के गठन की विरोधी थी और इसी कारण यहाँ की जनता में उसके खिलाफ नाराजगी है। लेकिन भाजपा को सबक सिखाने का जुनून राहुल गांधी पर इस कदर हावी है कि उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस की पांच साल की मेहनत पर पानी फेर दिया और दोबारा से केसीआर की सरकार बनवा दी। कांग्रेस को चंद्रबाबू नायडू से सावधान रहना चाहिए क्योंकि यदि आज वह उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से।

(साभार : पीएस)

खरी-खरी

कोई भी काम करो
पुरे दिल से करो।

"महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।"

अब हार ठीकरा आखिर किस पर

देश के तीन हिंदी भाषी राज्यों से बीजेपी का जाना क्या संकेत देता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने के बाद अब कई लोग यही बोल रहे हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो चला है। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शिवराज और रमन सिंह ने हार की जिम्मेदारी अपनी सिर पर ले ली...लेकिन क्या ये उनकी व्यक्तिगत हार थी। हम सभी ने टीवी पर देखा है इन चुनावों से पहले पार्टी को जब भी कहीं जीत मिलती थी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूरे जोश में पार्टी मुख्यालय पहुंचते थे और अपनी जय–जयकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का बखान करते थे। आज जब बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक साथ तीन प्रदेशों में उनकी हार कैसे हुई...तो हर किसी के पास रटा–रटाया जवाब है जी एंटी इनकैंबैंसी। रहने भी दो जनाब...अगर ये फार्मूला काम करता तो फिर शिवराज और रमन सिंह दोबारा जीत कर सत्ता में नहीं आते।

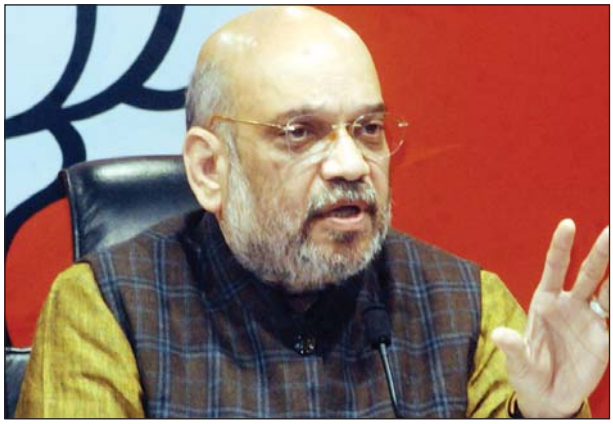

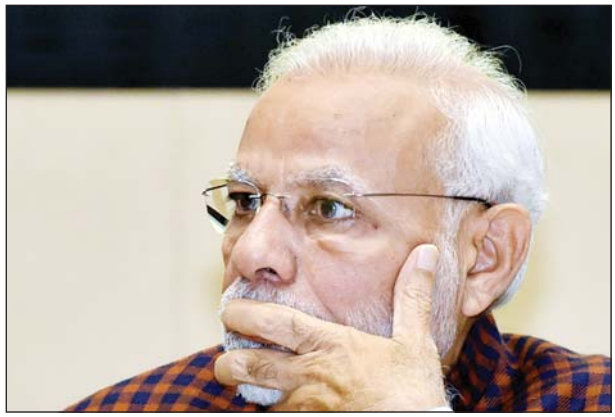

ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जीत और हार में सीटों का अंतर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह नहीं है...लेकिन हार तो हार होती है। पहले किसानों की नाराजगी, फिर एससी–एसटी एक्ट को लेकर सवर्णों का गुस्सा....अब बीजेपी के लोग भले ही इस बात को नहीं स्वीकारें....लेकिन इन दो मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसे बीजेपी नेताओं का अहंकार कहिए या कुछ और उन्हें लगने लगा था कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता।

कांग्रेस ने जहां मध्य प्रदेश में शिवराज को गद्दी से उखाड़ फेंका...वहीं छत्तीसगढ़ में पार्टी ने बंपर जीत हासिल की। रमन सिंह सरकार के खिलाफ लोगों में इस कदर नाराजगी थी कि पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर बात राजस्थान की करें तो वहां बीजेपी की हार पहले से तय थी। वसुंधरा ने 5 साल शासन जरूर किया लेकिन कई मौके ऐसे आए जब पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज उठी। किसानों का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी...वसुंधरा ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। कई लोगों का मानना है कि राजस्थान में बीजेपी की हार की वजह वसुंधरा का अहंकार है।

अब जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकल चुका है....राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है...क्या इन चुनाव परिणामों का असर अगले साल लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। अगर राजनीतिक पंडितों की मानें तो इन तीन राज्यों में हार के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करीब 30 से 35 सीटों का नुकसान हो सकता है। रही बात कांग्रेस की तो तीन राज्यों में मिली जीत अब उसके लिए संजीवनी का काम करेगी। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली सफलता से न सिर्फ राहुल का राजनीतिक कद बढ़ा है बल्कि उन्हें विपक्षी दलों की नजर में एक परिपक्व नेता के रूप में भी स्थापित कर दिया है। कुछ समय पहले तक मोदी का गुणगान करने वाले एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे भी राहुल की तारीफ करने से नहीं थक रहे। तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली कामयाबी पर राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि 'पप्पू' अब परमपूज्य हो गया है। राज ठाकरे ने सीधे–सीधे कहा कि विधानसभा चुनावों में मोदी और अमित शाह के चलते बीजेपी की हार हुई। राज ठाकरे ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने पिछले 4 साल से जैसा व्यवहार किया है उसके बाद तो ये होना ही था। एमएनएस की छोड़िए...एनडीए के घटक दल शिवसेना ने भी विधानसभा चुनावों में मिली बीजेपी की हार पर चुटकी ली है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा ये कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि लोगों का गुस्सा है। शिवसेना ने साफ–साफ कहा कि बीजेपी को आत्मचिंतन की जरूरत है। बताइए जो मोदी और अमित शाह कल तक भारत मुक्त कांग्रेस की बात कर रहे थे....आज उसी कांग्रेस ने उन्हें तीन हिंदी भाषी राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

(साभार : बीबीसी)

खरी-खरी

गोरक्षा के नाम पर अराजकता

"जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।"

चुनाव परिणामों ने उड़ा दी सभी एग्जिट पोल्स की धज्जियां

विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले विभिन्न टीवी चैनलों ने अपने एक्जिट पोलों के माध्यम से जो अनुमा. नित परिणाम जाहिर किये थे उनमें से कौन सही साबित हुए और कौन गलत, इस पर चिंतन करने की बजाय यदि सरसरी तौर पर देखें तो सभी एक्जिट पोल किसी भी पार्टी की जीत के अंतर का सही अनुमान लगाने में विफल रहे। इसके अलावा यदि इन चुनावों में नोटा को मिले भारी मतों को देखा जाये तो यकीनन राजनीतिक दलों के लिए यह बड़ी चेतावनी है कि वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की बजाय जनता की पसंद का उम्मीदवार उतारें। इन चुनावों से एक बात और साबित हुई कि मत प्रतिशत मामले में अभी भाजपा उतनी कमजोर नहीं पड़ी है जितना कांग्रेस समझ रही है। बात शुरू करते हैं एक्जिट पोलों से–

ज्यादातर एक्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिले भारी जनादेश का अनुमान लगाने में विफल रहे लेकिन मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर की उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। राजस्थान और तेलंगाना में एक्जिट पोलों में जिस दल के जीतने का अनुमान लगाया गया था, वह सच निकला। लेकिन मंगलवार को मतगणना के नतीजे सामने आने पर साबित हुआ कि विधानसभा चुनावों में वे जीत के अंतर का सही अनुमान नहीं लगा पाये।

राजस्थान

एक्जिट पोलों में राजस्थान में कांग्रेस की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाया गया था लेकिन नतीजा सामने आने पर पार्टी अपने बलबूते जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पायी और उसे 199 सीटों में से 99 सीटें मिली। वह बहुमत से बस थोड़ा पीछे रह गयी।

तेलंगाना

तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति को जबर्दस्त जीत मिली। उसे 119 सीटों में से 88 सीटें मिलीं और कांग्रेस महज 19 सीटों के साथ उससे काफी पीछे रह गयी।

मिजोरम

पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में कांग्रेस का सत्ता से सफाया गया और क्षेत्रीय दल मिजो नेशनल फ्रंट ने एक्जिट पोलों के अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन किया। उसने 40 में से 26 सीटें जीतीं।

मध्य प्रदेश

इस प्रदेश में नतीजा सामने आने के बाद कांग्रेस को 114 सीटें मिलीं जो 230 सदस्यीय विधानसभा में सामान्य बहुमत से दो कम है। भाजपा ने 109 सीटें हासिल कीं। एबीपी न्यूज ने भाजपा के लिए स्पष्ट हार (94) और कांग्रेस के लिए जीत (126) का अनुमान लगाया था। रिपब्लिक टीवी–जन की बात ने एक्जिट पोल में भाजपा को 128 सीटें दी थीं जबकि कांग्रेस को 95–115 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इंडिया टुडे एक्सिस ने कहा था कि भगवा दल को 102–120 और कांग्रेस को 104–122 सीटें मिलेंगी। टाइम्स नाउ–सीएनएक्स एक्जिट पोल में मध्यप्रदेश में भाजपा को 126 सीटें और कांग्रेस को 89 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में भाजपा 15 सीटों पर सिमट गयी और कांग्रेस को 68 सीटें मिलीं। अजीत जोगी की अगुवाई वाली जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़–बसपा गठबंधन सात सीटें हासिल कर पायी। घोषित नतीजों के विप. रीत एबीपी और टाइम्स नाउ–सीएनएक्स एक्जिट पोलों में भाजपा की जीत का अनुमान लगाया गया था। वैसे इंडिया टुडे–एक्सिस ने कहा कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उसके सीटों का अनुमान सही नहीं निकला।

वोट प्रतिशत

भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दी पट्टी के तीन अहम राज्यों को भले ही कांग्रेस के हाथों गंव दिया हो, लेकिन उसका वोट पूरी तरह से सबसे पुरानी पार्टी के पाले में नहीं गया। कुछ अन्य पार्टियों और निर्दलियों ने अपने मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। रोचक बात है कि मध्यप्रदेश में भाजपा का मत प्रतिशत कांग्रेस से थोड़ा अधिक ही रहा जबकि राजस्थान में कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा अधिक है। अगर इन विधानसभा चुनावों के मत प्रतिशत की तुलना 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से करें तो यह भाजपा के लिए बड़ी हार बताते हैं, क्योंकि इसने इन तीनों राज्यों की 65 लोकसभा सीटों में से 62 पर फतह हासिल की थी। (साभार : बीबीसी)

"जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं।"

सोशलः 'तो इन विधानसभा चुनावों में EVM ने ठीक काम किया'

पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है।

हालांकि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर जारी है।

राजस्थान में भी भाजपा पिछड़ रही है और कांग्रेस आगे चल रही है।

तेलंगाना में सत्ताधारी टीआरएस पूर्ण बहुमत की तरफ़ बढ़ती दिख रही है और मिज़ोरम में एमएनफ़ आगे है।

चुनाव के रुझानों पर लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

चुनावी रुझानों को देखकर अधि. कतर लोगों ने ईवीएम की कथित गड़बड़ी पर चुटकी ली है जिसे विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान एक मुद्दा बनाया था। कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने भी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर तीखे सवाल उठाए थे।

दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले फ़ेसबुक यूज़र कृष्णा पोफ़ले ने लिखा है, "हाँ भाई बताइये, कांग्रेस ने ईवीएम हैक किए हैं क्या?"

@RohitAgnibhoj नाम के ट्विटर यूज़र ने लिखा है, "तो आज म्टड ने ठीक काम किया। पूरी दुनिया के ईवीएम अचानक ठीक हुए।"

रेडियो जॉकी और कॉमेडियन अभिलाष थपलियाल ने लिखा है, "तो बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ईवीएम अब भी छेड़छाड़ की गई थी क्या?"

उत्तराखंड के गढ़वाल में रहने वाले संजय चंदोला ने लिखा है, "कांग्रेसियों को अभी ईवीएम पर भरोसा दिलाया जा रहा है, आगे 2019 भी तो है।" दीपेंद्र राजा पांडे ने फ़ेसबुक पर लिखा है, "गाय बचाते–बचाते भैंस पानी में जा रही है।" उमर अंसारी नाम के एक फ़ेसबुक यूज़र ने लिखा है, "मित्रों, भाजपा के साथ मॉब लिंचिंग हुई है।"

कुछ लोग चुनावी स्थिति क्लियर नहीं होने पर भी चुटकी ले रहे हैं। /ठंइन–ठींपलं नाम के एक ट्विटर यूज़र ने लिखा है, "सबसे पहले कांग्रेस को अपने सभी विजेता नेताओं को किसी सुरक्षित रिज़ॉर्ट में ले जाकर तालाबंद कर देना चाहिए क्योंकि अमित शाह घर से निकल चुके हैं।"

प्रोफ़ेसर शिवानी नाग ने लिखा है, "योगी जी अब हार का नाम बदलकर जीत न कर दें।"

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसे उन्होंने तथाकथित मोदी लहर की मौजूदा स्थिति बताया है।(साभार : इंटरनेट)

EVM पर सवाल न उठें इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत कुछ करना होगा

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो गये हैं और इन चुनावों के जो परिणाम आयेंगे वे आने वाले समय में भारत की राजनीति की दिशा तय करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन चुनाव परिणामा. ˇ को प्रभावित करने के लिये ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की आशंका करते हुए ट्विट किया और प्रत्येक कांग्रेसी को ईवीएम मशीनों की पहरेदारी पूरी मुस्तैदी से करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि संवैधानिक संस्थाओं पर पदासीन अधिकारियों पर सत्ता से प्रभावित होने की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या यही लगाया जाये कि लोगों का लोकतान्त्रिक प्रणाली के आधारभूत स्तम्भ 'चुनाव आयोग' पर से भरोसा उठ चुका है ? अगर ऐसा है तो बड़ा प्रश्न यह है कि लोकतंत्र को शुद्ध सांसें कैसे मिलेंगी ? लोकतंत्र श्रेष्ठ प्रणाली है। पर उसके संचालन में शुद्धता हो। लोक जीवन में लोकतंत्र प्रतिष्ठापित हो और लो. कतंत्र में लोक मत को अधिमान मिले।

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनाव है, यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है। लोकतंत्र में स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिये चुनाव की स्वस्थता एवं पारदर्शिता अनिवार्य है। इनको बनाये रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि चुनावों में हार–जीत किस पार्टी की होगी, उसका मतलब केवल इससे रहता है कि मतदाताओं के मत की पवित्रता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। बेशक ईवीएम मशीनों को लेकर विपक्षी दल पिछले लम्बे अरसे से आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। सच्चाई यह भी है कि भले ही इन मशीना. ˇ का प्रयोग विभिन्न राज्यों के चुनावों में मौजूदा भाजपा सरकार के सत्ता में रहते हुआ है और इनमें से कुछ राज्यों में विपक्षी कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी है। बावजूद इसके सच्चाई यह भी है कि हर चुनाव में आयोग के पास मतदान में धांधली होने की शिकायतें बढ़ी हैं।

हमारी लोकतंत्र प्रणाली में तंत्र ज्यादा और लोक कम रह गया है, यह एक सोचनीय स्थिति है। यह प्रणाली उतनी ही अच्छी हो सकती है, जितने कुशल चलाने वाले होते हैं। आज बड़े–बड़े राष्ट्रों के चिन्तन, दर्शन व शासन प्रणाली में परिवर्तन आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं। अब तक जिस विचारधारा पर चल रहे थे, उसे किनारे रखकर नया रास्ता खोज रहे हैं। परिवर्तन अच्छी बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो, मतदाता स्तर पर भी और प्रशासक स्तर पर भी। लोक चेतना जागे। ताकि चुनाव की पवित्रता को धुंधलाने के प्रयास करने वाले दो बार सोचें। (साभार : इंटरनेट)

एक देश नारे लगाने से महान नहीं बन जाता.

मत प्रतिशत के मामले में नोटा ने तमाम दलों को मात दी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सभी उम्मीदवारों को खारिज करने (नोटा) के विकल्प को भी मतदाताओं ने तमाम क्षेत्रीय दलों से ज्यादा तरजीह दी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 2.1 प्रतिशत वोट नोटा के खाते में गये। जबकि मिज़ोरम में नोटा का प्रतिशत सबसे कम (0.5 प्रतिशत) दर्ज किया गया। चुनाव वाले राज्यों में नोटा का मत प्रतिशत आप और सपा सहित अन्य क्षेत्रीय दलों से अधिक दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ की 90 में से 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही आप को 0.9 प्रतिशत, सपा और राकांपा को 0.2 तथा भाकपा को 0.3 प्रतिशत वोट मिले। वहीं राज्य के 2.1 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा को अपनी पसंद बनाया।

मध्य प्रदेश में 1.5 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा को अपनाया जबकि सपा को राज्य में एक और आप को 0.7 प्रतिशत वोट मिल सके। इसी तरह राजस्थान में माकपा को 1.3 प्रतिशत और सपा को 0.2 प्रतिशत मिले मतों की तुलना में राज्य के 1.3 प्रतिशत मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों को नकारते हुये नोटा को अपनाया। कमोबेश यही स्थिति तेलंगाना में भी देखने को मिली। राज्य में माकपा और भाकपा को 0.4 प्रतिशत और राकांपा को महज 0.2 प्रतिशत मत से संतोष करना पड़ा जबकि नोटा के खाते में 1.1 प्रतिशत मत पड़े। नोटा को इतनी अधिक संख्या में मतदताओं द्वारा अपनाये जाने से राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है।(एजेंसी)

सुब्रमण्यम स्वामी की नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नसीहत

विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि किसी को भी खुद को जनता का ठेकेदार नहीं समझना चाहिए और पार्टी को जागने की ज़रूरत है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "हम तो कहते थे जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे लेकिन जनता के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इंदिरा गांधी भी यही समझती थीं लेकिन क्या हुआ? वो खुद हार गईं।" अपनी बेबाकी के लिए जाने जानेवाले स्वामी ने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन लोगों को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का वो बयान याद होगा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2019 वो जीतेंगे और उसके बाद अगले 50 सालों तक पार्टी देश में शासन करेगी। सितंबर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात मीडिया को बताई थी।

मंगलवार को आए चुनाव नतीजे में बीजेपी को हिंदी पट्टी के तीन राज्यों– मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस तीनों सूबों में सरकार बनाने की प्रक्रिया में है।

लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इन वोटों को कांग्रेस के पक्ष में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा कांग्रेस को दोनों में से किसी राज्य में बहुमत नहीं मिला है।

स्वामी ने कहा, "उत्तर–पूर्वी राज्य मिज़ोरम जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, वहां वो हार गई है और दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।"

भाजपा के राज्य सभा सांसद का कहना था कि चुनाव नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि पब्लिक बीजेपी को जगाना चाहती थी। उनका कहना था कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से किसान और व्यापारियों में नाराज़गी है। ये लोग परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थक रहे हैं।

वो विदेशों से काला धन वापस लाने के बीजेपी का वादे पूरा न हो पाने को भी जनता की नाराज़गी की वजह मानते हैं और दावा करते हैं कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में दिए जाने का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो पूरा होगा। स्वामी ये भी कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी को ज़ोर–शोर से काम करना होगा। हालांकि इस मामले को वो अदालत के ज़रिए सुलझाना चाहते हैं जहां उनकी एक याचिका लंबित है। आरएसएस और वीएचपी राम मंदिर निर्माण के लिए क़ानून लाने की मांग कर रहे हैं लेकिन स्वामी का कहना है कि क़ानून या विधेयक लाए जाने के मामले पर वो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उससे जो क़ानूनी प्रक्रिया उन्होंने अदालत में चला रखी है उसको नुक़सान हो सकता है।

शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किए जाने पर सुब्रमण्यम स्वामी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि वो नहीं समझ सकते हैं कि जिस आदमी को उन्होंने वित्त मंत्रालय से बाहर करवाया था, उसे देश के केंद्रीय बैंक का मुखिया कैसे बना दिया गया। उनका कहना था कि उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री को लिखा है।

(एजेंसी)

खरी-खरी

जैसा आप सोचतें हो
वैसा आप बन जाते हो

अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है।

पांच राज्यों में भाजपा के हारते ही मोदी को हटा कर योगी को लाने की बात शुरू

हिन्दी पट्टी के तीन राज्यों से सत्ता गंवाने के बाद भाजपा सदमे में है। भले ही भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता हार के अलग–अलग कारण गिनाये, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस ने भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले हार की गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं भाजपा के कांग्रेस मुक्त गुब्बारे की हवा भी निक. ालने का काम किया है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस के खुशखबरी तो हैं ही वहीं इन नतीजों ने आईसीयू में पड़ी कांग्रेस में प्राण फूंकने का काम किया है। महागठबंधन की जोर पकड़ती मुहिम में मनमाफिक नतीजों से विपक्ष का साहस दोगुना हुआ है। कुल मिलाकर इन चुनाव नतीजों ने जहां मोदी–शाह की जोड़ी के तिलस्म को चकनाचूर किया है। वहीं इन चुनाव नतीजों ने भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिये नये सिरे से सोचने के मजबूर कर दिया है। हिंदी हार्टलैंड ही बीजेपी का गढ़ बना था। उसमें सेंध लगाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही है। हालांकि कांग्रेस की असली चुनौती यूपी में है। फिलवक्त ये भाजपा के लिये गहरे चिन्तन और मनन का वक्त है। अगर मतदाताओं का मनोभाव अगले तीन–चार महीनों तक ऐसा ही रहा तो भाजपा दिल्ली की गद्दी भी गंवा बैठेगी।

तीन राज्यों में से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की डेढ़ दशक पुरानी सरकारों को कांग्रेस ने आखिरकर कांग्रेस ने उखाड़ डाला है। सबसे ज्यादा चमत्कार छत्तीसगढ़ में हुआ। वहां तो भाजपा के बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान व मध्यप्रदेश में कांग्रेस–भाजपा की कड़ी टक्कर में आखिरकार मुकाबला कांग्रेस ने जीता। भाजपा इन तीन राज्यों में 'एंटी इनकम्बैंसी' को प्रमुख वजह बता रही है, लेकिन हार का ठीकरा 'एंटी इनकम्बैंसी' पर नहीं फोड़ा जा सकता। इस हार के बाद ब्रांड मोदी की लोकप्रियता पर भी असर डाला है। विदेशी अखबारों में इस बाबत लंबी रपटें प्रकाशित हुई हैं।

लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में जाकर रैलियां कीं और राजस्थान में तो पूरा जोर लगा दिया था। वो अ ल ग बात है ि क

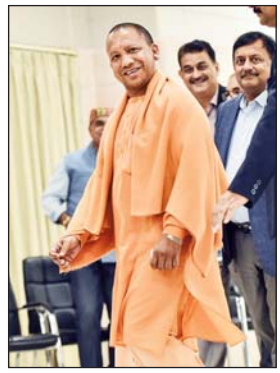

रणनीति के तहत पीएम मोदी की कम रैलियां रखी गयी थीं, ताकि हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर फोड़ा जा सके। असल में बीजेपी भी पूरे प्रचार में इसी पर फोकस कर रही थी कि 2019 में फिर से मोदी को लाने के लिए इन राज्यों में बीजेपी की जीत जरूरी है। कांग्रेस अगर इन राज्यों में बीजेपी को मात देकर मोदी की उस अजेय इमेज को बुरी तरह तोड़ दिया है जो इमेज बीजेपी दिखाने की कोशिश करती रही है।

बेशक इन जनादेशों के बाद, कमोबेश उत्तर भारत में, कांग्रेस का नये सिरे से पुनरोत्थान होना तय है, जहां इन राज्यों में ही लोकसभा की 65 सीटें हैं। अब इन जनादेशों के बाद कांग्रेस के सहयोग से महागठबंधन बनाने के प्रयास तेज और सार्थक हो सकते हैं,लेकिन तेलंगाना में कथित महागठबंधन बिल्कुल नाकाम रहा। राजस्थान में पांच साल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 15 साल से चल रहा वनवास राहुल गांधी की अगुवाई में खत्म हुआ है। जो कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। इस हार के बाद मोदी–शाह की जोड़ी के लिये पार्टी के अंदर और बाहर मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। तीनों राज्यों में हार से लोकसभा चुनाव के पहले ही मोदी और अमित शाह की जिताऊ क्षमता और कार्यप्रणाली पर घर के भीतर से ही सवाल उठेंगे और जिन लोगों को किनारे बिठा रखा गया है वे मुखरित हो उठेंगे। इसके प्रारंभिक संकेत मप्र में बाबूलाल गौर और रघुनंदन शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं के ताजा बयानबाजी से मिल ही चुके हैं। इस जनादेश के बाद भाजपा में मोदी विरा. ेधी गुट मुख होगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

वहीं चुनाव नतीजों के बाद लखनऊ में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के नए होर्डिंगों पर विवाद पैदा हो गया है। लखनऊ में लगे इन होर्डिंगों में 'योगी लाओ, देश बचाओ; लिखा है। साथ ही 10 फरवरी 2019 को राजधानी लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में धर्म संसद आयोजित करने की बात कही गई है। होर्डिंगों में 'जुमलेबाजी का नाम मोदी' 'हिंदुत्व का ब्रांड योगी' के साथ 'हैशटैग योगी फॉर पीएम' लिखा है। इसके साथ ही दोनों के किए गए कार्यों का विवरण होर्डिंगों में लिखा है। ये होर्डिंग शहर में पांच राज्यों में बीजेपी की हार के बाद रातों–रात लगाए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में पहली बार कांग्रेस भाजपा को करारी शिकस्त देने में सफल हो पायी है। चुनाव नतीजे विपक्ष के लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। उम्दा नतीजों के बाद कांग्रेस फिर से सेंटर पॉइंट में दिखेगी और विपक्षी एकता की धुरी बनने की फिर एक कोशिश हो सकती है।

(साभार : पीएस)

अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलो।

मंदसौर में किसानों की मौत के बावजूद कैसे जीती भाजपा

पंद्रह साल के वनवास के बाद आख़रिकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।

लेकिन एक बात जो कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही है, वो ये कि मंदसौर की चार सीटों में से भाजपा तीन सीटें कैसे जीत गई।

आठ जून 2017 को पुलिस फ़ायरिंग में मंदसौर में छह किसान मारे गए थे। पिछले कुछ वक़्त से देश के अलग–अलग हिस्सों में किसान आंदोलन करते रहे हैं लेकिन इस घटना ने किसानों की नाराज़गी को और बढ़ाया था।

भाजपा ने इस घटना में कांग्रेस से जुड़े समाजविरोधी लोगों का हाथ बताया था, लेकिन ऐसी ख़बरें आईं कि स्थानीय पाटीदार किसान इस कारण भाजपा से बेहद नाराज़ थे।

भाजपा के सुधीर गुप्ता और कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कई नेताओं ने मंदसौर का दौरा किया था।

मरने वालों में चार– अभिषेक, बबलू, कन्हैयालाल, चैनराम का ताल्लुक पाटीदार समुदाय से था।

मंदसौर की चार सीटों– मलारगढ़ रिज़र्व, मंदसौर प्रॉपर, सुवासरा और गरोढ में पाटीदार समुदाय के 60–70 हज़ार वोट है।

सुवासरा में कांग्रेस की विजय हुई जबकि बाक़ी सीटें भाजपा के खाते में गईं। भोपाल में किसान नेता शिवकुमार शर्मा नतीजों से चकित हैं और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अन्नदाता अधिकार यात्रा की, "सात हज़ार किलोमीटर की दूरी तय की, पुलिस की गोली में छह किसान मारे गए, सात हज़ार किसानों पर फ़र्ज़ी मुकदमें बने", उसके बावजूद ऐसे नतीजे क्यों आए, ये उनकी समझ से बाहर हैं। मंदसौर में पाटीदार समाज ज़िला अध्यक्ष अमृतराम पाटीदार ईवीएम से जुड़े आरोपों को ख़ारिज करते हैं, लेकिन कहते हैं उनको "समझ नहीं आ रहा है" कि भाजपा कैसे जीत गई। वो कहते हैं, "वोट के दो दिन पहले तो लोग कह रहे थे कि वो भाजपा के खिलाफ़ वोट देंगे लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने फिर भी भाजपा को ही वोट दिया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए उम्मीदवारों के लोग बाहर पहरा दे रहे थे।" मंदसौर में स्थानीय पत्रकार आक. ाश चौहान भी नतीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि मीडिया में किसानों की ऐसी तस्वीरें और कहानियां आई थीं जिनके मुताबिक किसान अपना माल कौड़ियों में बेच रहे थे। अख़बार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ किसान लहसुन दो रुपए किलो के दाम पर बेचने को मजबूर थे।

मध्य प्रदेश में क़रीब 70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर खेती से जुड़े हैं। मंदसौर राज्य के मालवा निमाड़ का हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कृषि का इलाक़ा है। मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन के निदेशक और लो. कनीति–सीएसडीएस के स्टेट कोआर्डिनेटर यतींद्र सिंह सिसोदिया के अनुसार प्रदेश में किसानों की नाराज़गी को बढ़ाचढ़ाकर पेश किया और सरकार की कई स्कीमों के कारण किसान खुश थे। शायद किसानों को एक ब्लॉक की तरह लेना, समझना सही नहीं होगा। किसान छोटे और बड़े होते हैं। ऐसे किसान होते हैं जो किराए की ज़मीन पर काम करते हैं। इसके अलावा खेत में काम करने वाले मज़दूरों की भी अच्छी खासी तादाद है। यतींद्र सिंह के मुताबिक, जहां बड़े और मंझले किसानों ने भाजपा के पक्ष के वोट दिया, छोटे किसानों और मज़दूर कांग्रेस के पक्ष में रहे।

पाटीदार लंबे समय से भाजपा को वोट देते आए हैं। यतींद्र सिंह कहते हैं, "किसान सरकार से नाराज़ हैं, इस सोच ने कांग्रेस को साथ लाने में मदद की लेकिन ऐसा नहीं है कि किसानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया।" शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को रिझाने के लिए कम ब्याज़ पर ऋण देना, भावांतर स्कीम जैसी योजनाएं लागू की।

भावांतर स्कीम में किसानों को सरकारी दाम और जिस दाम पर माल बिका, उसका अंतर दिया जाता है, लेकिन आरोप लगे कि बिचौलियों ने इस स्कीम का जमकर दुरुपयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दो लाख रुपए तक की कर्ज़ माफ़ी के वादे ने किसानों को उनकी पार्टी की ओर मोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि राज्य की आर्थिक खस्ताहाली के बीच ये वादा कैसे पूरा होगा। आर्थिक मामलों के जानकार आरएस तिवारी के मुताबिक राहुल गांधी के वादों को पूरा करना संभव नहीं है। वो कहते हैं, "राज्य सरकार आरबीआई से ऋण लेने की सीमा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई है। अगर और कर्ज़ लिया गया तो वो सीमा पार हो जाएगी और ओवरड्राफ़्ट लेना होगा।

कई किसानों ने इस कारण ऋण की किश्तें देने के साथ–साथ फसल बीमा का प्रीमियम देना बंद कर दिया है।" भाजपा को मालवा निमाड़ से बड़ी उम्मीद थीं लेकिन वहां 66 सीटों में पार्टी को इस बार पिछली बार से भी आधी सीटें यानी 28 सीटें ही मिलीं। महाकौशल, ग्वालियर चंबल, मध्य भारत और बुंदेलखंड में भी भाजपा को भारी नुकसान हुआ। याद रहे मालवा निमाड़ में जनसंघ के वक़्त से ही आरएसएस का गढ़ रहा है और वहां भाजपा का अच्छा परफॉर्म ना कर पाना पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा।

(साभार : पीएस)

खरी-खरी

ताकत जीवन है,
कमजोरी मृत्यु है।

जिन्दगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कन्धों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।

पाप बढ़ा जब–जब धरती पर आये बारंबार

राजेश्वर राय 'दयानिधि'

हम हैं अब भी पराधीन आज़ादी तुम्हें मुबारक हो
मेरे पैसों की पश्मीना–खादी तुम्हें मुबारक हो
लील गयी जो लाखों जानें कहो उसे ना करने को
राजनीति ऐसी हराम की ज़ादी तुम्हें मुबारक हो
हम दो एक हमारे होगा लड़का–लड़की चाहे जो
भुखमर्रों से भरी हुई आबादी तुम्हें मुबारक हो
बहुत हुआ बर्बाद आज से छोड़ रहा हूँ मैं मित्रों!
अंग्रेजी से ले महुए की बादी तुम्हें मुबारक हो
मैं उसको ही चाहूँगा जो प्यार लुटाये बदले में
नखरोंवाली,नाकचढ़ी प्रतिवादी तुम्हें मुबारक हो
मैं ऐरेंज करूँगा मैरिज माँ–बाबू की मर्ज़ी से
प्रेम–पलायन वाली मित्रों शादी तुम्हें मुबारक हो
मैं तो बिना लोभ के कमसिन से ही व्याह रचाऊंगा
खूब कमाती नोटों वाली दादी तुम्हें मुबारक हो
कुछ तो लत्ते भेज बहू मैं गाँव पड़ी चकती में हूँ
बाकी तेरे वार्डरोब की लादी तुम्हें मुबारक हो
छोटी नाली हूँ पर निर्मल–शीतल नीर बहे मुझमें
नदियों तुममें भरी हुई ये गादी तुम्हें मुबारक हो
मेरा दिल जो घर था तेरा तुमने ही खुद तोड़ दिया
तेरे हाथों तेरी ही बर्बादी तुम्हें मुबारक हो
अलग हुआ है तू बन्धन से,दोष बहू को मत देना
जो जी आये कर बेटे, आज़ादी तुम्हें मुबारक हो
मैं हूँ ऐश–कैश का हामी जुदा राह अब अपनी है
तेरी 'राज' ज़िन्दगी सीधी–सादी तुम्हें मुबारक हो
सहस्त्रों साल से संसार में.....शोषित जो नारी है
वो साबित कर चुकी है अब नहीं हरगिज़ बेचारी है

बी–59/गरिमा गार्डन /साहिबाबाद
गाजियाबाद /उत्तर प्रदेश 201005 8800201131/9540276160

पंडित सुरेश नीरव

ये गठबंधन सियासत का अजब मंज़र दिखाता है,
जो अक्सर घोषणा करने से पहले टूट जाता है।
जो मुर्गा बांग देकर सारी दुनिया को जगाता है,
छुरी चलने से पहले पेटभर दाने वो खाता है।
जो वादे ओढ़ता है और वादों को बिछाता है,
वो मतदाता तो भूखे पेट भी नारे लगाता है।
वो रोता है कभी खुद पर कभी खुद को हंसाता है,
मगर लंगड़ी सियासत में कलाबाजी दिखाता है।
वो जब पिछड़े हुए लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है,
वो शातिर भेड़िया है भेड़ की सूरत में आता है।
वो जनता को फक़्त बारात की घोड़ी समझता है,
जिसे अपने इलेक्शन में वो जीभर कर सजाता है।
किसी भी पक्ष की बातें उसे अच्छी नहीं लगतीं,
वही नेता सफल है जो अलग भौंपू बजाता है।
सियासत की अजब बारात है किस से कहें 'नीरव',
जो फूफा को मनाते हैं तो मामा रूठ जाता है।

कहानी

एक जवान बेटे ने घर में टीवी पर जब देश के पीएम का ये भाषण सुना कि 60 वर्षो से सत्ताधारी सरकारों ने कुछ नही किया उन्होंने देश को लूटने का ही काम किया। तब उस बेटे ने अपने पिता से पूछा की पापा क्या ये सत्य हे? क्या देश की जनता मुर्ख थी ?जो मतदान पूर्वक ऐसी सरकारे चुनती रही। अगर सत्ताधारी प्रमुख ऐसे भ्रष्ट थे तो उनको सजा क्यों नही मिली? क्यों आजतक हम इन्हें महापुरुषो में गिनते हे ? बेटे के ऐसे सवाल पर पिता ने कहा की बेटा इसकी हकीकत जाननी हे तो एक काम करते हे अपने पूरे परिवार के सदस्य कल बिजली, वाहन,मोबाइल ,गैस रहित मनाएंगे और इनसे सम्बन्धित किसी भी वस्तु का प्रयोग नही करेंगे। अगले दिन प्रातः घर की महिलाएं कुए से पानी लाई ,थके हाल लकड़ी जलाकर चूल्हे से खाना बनाया , पैदल ही 1 किमी दूर दूकान पर धंधा करने गए ,बिना पंखे के गर्मी में बेहाल दूकान में व्यापार किया ,आवश्यक होने पर भी व्यापारी और ग्राहक से बात करने मोबाइल का प्रयोग नही कर पाए ,रात को पैदल ही थके थके घर आये ,घर की महिलाए दिनभर काम करके गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाकर लतपथ हो गयी थी फिर लालटेन की रौशनी में सबने खाना खाया। अंत में टीवी बन्द होने से जल्दी जब सोने गये लेकिन गर्मी में बिना पंखे की नींद नही आयी तब घर के सभी सदस्य बोले पापा जी ऐसी जिंदगी तो अब एक पल भी ओर नही जी सकते आगे कभी ऐसा प्रयोग नही करवाना। तब पापा बोले –बेटा तुम एक दिन में ही इतने अधीर हो गए तो सोचो आज से 50–60 वर्ष पूर्व तुम्हारे बाप–दादा ऐसी ही जिंदगी जीते थे लेकिन ये आज की जो इतनी सुविधाओं की जिंदगी देख रहे हो वो हमारी चाहत,मेहनत और 60 वर्षो में देश की सत्ताधारी सरकारों के प्रयासो से प्राप्त हुई है। सड़के, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, गैस चूल्हे, दूरसंचार फोन की सुविधाएं सब विभिन्न सरक. ारी प्रयासों से सम्भव हुई है।

इस दुनिया में अपनी तुलना किसी से भी मत करो अगर आप ऐसा करते हो तो आप स्वयं को बेइज्जत कर रहे हो।

मोदी–शाह के लिए ख़तरे की घंटी हैं या नहीं?

विधानसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण अभी कुछ वक्त तक जारी रहेगा लेकिन अब तक जितनी जानक. ारी सामने आई है, उनके आधार पर ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ख़तरे की घंटी है?

2014 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद से, बिहार, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, बीजेपी को कई छोटी–बड़ी हारों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह झटका काफ़ी बड़ा है। 'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा देने वाली पार्टी से कांग्रेस ने तीन बड़े राज्य छीन लिए हैं।

लेकिन इन नतीजों के आधार पर 2019 के लिए कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाज़ी होगी, ऐसा मानने की कई वजहें हैं।

सबसे पहली बात तो यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब चार महीने बचे हैं, अभी जो चुनावी गहमागहमी दिख रही है वह लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर पार्टियों के मनोबल पर असर डालते हैं लेकिन उनकी अहमियत को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है।

अंग्रेज़ी का मुहावरा उधार लें तो 'राजनीति में एक हफ़्ता बहुत लंबा समय होता है', अभी तो चार महीने बाकी हैं। साथ ही, यह भी याद रखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लोग अलग–अलग तरीके से वोट देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, फ़रवरी 2015 में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली थीं, जबकि कुछ ही महीने पहले मोदी लहर से केंद्र में सरकार बनी थी।

यह भी समझना चाहिए कि मोदी ने संसदीय चुनावों को अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव की तरह बना दिया है। 2014 की ही तरह, 2019 का चुनाव भी वे अपनी निजी लोकप्रियता के आधार पर लड़ेंगे, जिसमें मुख्य संदेश यही होगा कि मोदी नहीं तो क्या राहुल गांधी?

लेकिन यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यह दांव काम कर जाए। जिन लोगों को 2004 के लोकसभा चुनाव याद हैं, वे जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने लोक. प्रिय नेता थे और उनके सामने एक 'विदेशी मूल' की महिला थी जो ठीक से हिंदी बोल नहीं पाती थी, और तब इंडिया शाइन कर रहा था। उस समय पार्टी के सबसे तेज़–तर्रार माने जाने वाले नेता, प्रमोद महाजन ने पूरे जोश और आत्मविश्वास से जीत की भविष्यवाणी की थी।

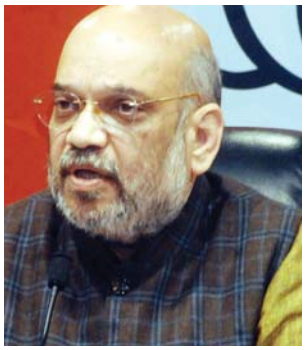

उनकी इस भविष्यवाणी से राजनीति करने वालों, और उस पर टिप्पणी करने वालों को सीखना चाहिए कि भविष्यवाणियां अक्सर ग़लत साबित होती रहती हैं। भारत का वोटर कब क्या जनादेश देगा, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि 2004 से लेकर अब तक भारत की राजनीति बहुत बदल चुकी है लेकिन एक बात नहीं बदली है, वह है मतदाता के मन की गुत्थियां सुलझा पाने में बार–बार मिलने वाली नाकामी।

2004 की थोड़ी और चर्चा कर लें तो शायद 2019 की थाह लेने में कुछ मदद मिले। यह अपने–आप में कम दिलचस्प बात नहीं है कि 2003 में हुए विधानसभा चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीन लिए थे।

अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी जीत के बाद अति–आत्मविश्वास में लोकसभा चुनाव जल्दी कराने का फैसला किया था। उस वक़्त बीजेपी की सोच थी कि वाजपेयी के कद के सामने सोनिया गांधी टिक नहीं पाएंगी, लेकिन जैसा दिसंबर में सोचा था, वैसा मई में नहीं हुआ। बीजेपी चुनाव हार गई और सरकार कांग्रेस ने बनाई।

कांग्रेस को कड़ी मेहनत के बाद तीन राज्यों में कामयाबी तो मिली है, लेकिन इसे 2019 में जीत की गारंटी नहीं माना जा सकता, ऐसा सोचना जल्दबाज़ी होगी। कांग्रेस की ताज़ा कामयाबी को गौर से देखें तो कई छोटी–बड़ी बातें समझ में आती हैं।

पहली बात तो ये है कि दो बड़े राज्यों–मध्य प्रदेश और राजस्थान–में कांग्रेस और बीजेपी के वोटों का प्रतिशत लगभग एक बराबर है, रुझान के समय के चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रहे हैं कि दोनों के बीच का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रतिशत का है।

इस बहुत कम अंतर का मतलब है कि इस चुनाव के परिणाम मोदी की लोकप्रियता में किसी बड़ी गिरावट का संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि राहुल गांधी उनके सामने एक चुनौती के तौर पर उभर ज़रूर रहे हैं। यह चुनौती और बीजेपी मोदी–शाह की रणनीति अगले चार महीने में कई दिलचस्प सियासी खेल दिखाएगी।

इसका यह नतीजा भी नहीं निकालना चाहिए कि 2019 में मोदी की वापसी तय है, बहुत सारे फ़ैक्टर बीजेपी के अनुकूल नहीं हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बेहद मज़बूत मानी जाती रही है, इन राज्यों में कुल मिलाकर 65 लोकसभा सीटे हैं। मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं।

(एजेंसी)

कोशिश करो और असफल हो जाओ, पर कोशिश करने में असफल मत होना।

मध्य प्रदेश में सवर्ण समाज की नाराजगी के चलते जीती बाजी हार गयी भाजपा

सबका साथ सबका विकास के ध्येय को लेकर आगे बढ़ने का दावा करने वाली मोदी सरकार को पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुँह की खानी पड़ी है। उसका अपना वोट बैंक तो सरका ही है साथ ही चुनावों के दौरान उसने कई आत्मघाती कदम भी उठाये। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के जो परिणाम जारी किये हैं उनका विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि भले संख्या के मामले में कांग्रेस आगे निकल गयी हो लेकिन 15 साल शासन में रहने के बावजूद उसने कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दी है। राजनीति चूँकि अंकगणित का खेल है इसलिए भले कोई एक सीट ज्यादा जीते गद्दी उसे ही मिलती है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में राजनी. तिक दलों को मिले मतों पर नजर डालें तो भाजपा 41 प्रतिशत मतों के साथ पहले नंबर पर रही और उसे कुल 15642980 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस 40 ।9 प्रतिशत मतों के साथ दूसरे नंबर पर रही और उसे कुल 15595153 मत मिले। यानि भाजपा को कांग्रेस से मात्र 47827 मत मिले। अब क्षेत्रीय दलों को कितने मत मिले इसको अगर छोड़ भी दें तो दो आंकड़े जरूर चौंकाते हैं। पहला यह कि ैब्ैज एक्ट मामले से नाराज सवर्णों की जो पार्टी सपाक्स नाम से विधानसभा चुनाव लड़ रही थी उसने कुल 156486 मत हासिल किये। यानि अगर सपाक्स के मत भाजपा के साथ जुड़ जाते तो स्थिति बदल सकती थी। यही नहीं नोटा को बड़ी संख्या में (542295) मत मिले। यानि इतने ज्यादा मतदाता किसी भी दल के उम्मीदवार से खुश नहीं थे। मतदाताओं की उम्मीदवारों के प्रति यह नाखुशी राजनी. तिक दलों के लिए चेतावनी होनी चाहिए। मतदाता अब यह सहन नहीं करता कि आप किसी को भी उम्मीदवार बना दें तो लोग उसे या इसे मतदान करने को बाध्य होंगे ही। नोटा के प्रति मतदाताओं का यह आकर्षण यदि लोकसभा चुनावों में भी जारी रहा तो नुकसान सभी दलों को होना तय है।

सवर्ण समाज का गुस्सा भारी पड़ा

अब बात जरा सपाक्स की हो जाये। यह सही है कि सरकार को सभी जातियों और वर्गों का ध्यान रखना है। कोई वर्ग उपेक्षित है तो उसे राहत भी प्रदान करनी है। लेकिन उपेक्षितों को आगे लाते समय अन्यों की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है एससी–एसटी एक्ट मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का जो फैसला पलटा था उसका सवर्णों में गलत संदेश गया और सरकार इस वर्ग की चिंताओं को दूर करने में नाकामयाब रही। ऐसे में सवर्णों की ओर से कई प्रदेशों में नोटा पर बटन दबाने का अभियान चलाया गया और अलग से पार्टी सपाक्स बनाकर उम्मीदवार मैदान में उतारे गये जिसने भाजपा का मूल वोट बैंक समझे जाने वाले सवर्ण समाज में सेंध लगा दी। नतीजा सामने है। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा को एक सबक देकर यह लोग संतुष्ट हो गये हों आगे के चुनावों में क्या हो सकता है इसके प्रति भी चिंता करनी चाहिए। यदि एससी–एसटी एक्ट मामले से पहले के राज्य के माहौल पर गौर किया जाये तो शिवराज सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल इतना नहीं था कि सत्ता पलट जाये।

मुस्लिम मत एकजुट होकर कांग्रेस को गये

भाजपा की ओर से इन चुनावों में कई आत्मघाती कदमों को उठाया गया लेकिन यदि कुछ की चर्चा कर ली जाये तो उनमें से एक कमलनाथ का वह वायरल वीडियो भी है जिसमें वह मुस्लिम मतों की बात करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो भाजपा ने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने की मंशा से इतना वायरल कर दिया कि प्रदेश के कोने–कोने में यह संदेश पहुँच गया कि यदि भाजपा को हटाना है तो एकजुट होकर कांग्रेस को मतदान करना होगा। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुस्लिम समाज का एकमुश्त वोट मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'आपको अली मुबारक, हमको बजरंग बली...' वाला बयान और हनुमानजी को दलित बताने वाला बयान भी भाजपा को जबरदस्त नुकसान पहुँचाने वाला रहा है।

शिवराज को हराने पर तुले थे भाजपा के ही नेता

यह सही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में थी लेकिन पार्टी में अब कई नेता ऐसे हो गये थे जोकि शिवराज को हराने पर तुले थे। उनका प्राथमिक उद्देश्य शिवराज को गद्दी हासिल करने से रोकना था। (साभार : बीबीसी)

खरी-खरी

"कानून जितने ज्यादा होते हैं, न्याय उतना ही कम होता है।"

जो अपने ऊपर आश्रित व्यक्तियों को बांटे बिना ही उत्तम भोजन करता है उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा ?

तेलंगाना में पूरे नहीं हुए कांग्रेस–बीजेपी के सपने...

तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) ने राज्य के विधानसभा चुनाव में 88 सीटों के साथ ज़बरदस्त जीत हासिल की है।

राज्य में सात दिसंबर को चुनाव हुए थे, जिनमें टीआरएस को कांग्रेस के गठबंधन की ओर से कड़ी टक्कर मिलने की बात कही गई थी।

लेकिन मंगलवार को जब नतीजे आए तो टीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव का जादू चलता दिखा।

राज्य विधानसभा को भंग कर समय से पहले चुनाव कराने का टीआरएस प्रमुख का फ़ैसला काम कर गया।

किसानों और दूसरे कमज़ोर तबकों के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं ने केसीआर को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

ग्रामीण सीटों पर मिला फ़ायदा

टीआरएस पार्टी की जीत का श्रेय किसानों और ग्रामीण मतदाताओं को जाता है। तेलंगाना की ग्रामीण सीटों पर पार्टी को मिले वोट प्रतिशत से ये बात साफ दिखती है। टीआरएस सरकार ने किसानों के लिए रैयत बंधु और रैयत भीम जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं। इन योजनाओं के चलते केसीआर को किसानों के बीच काफी लोकप्रियता मिली। इसके अलावा किसानों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराना, मिशन काकटेय और कालेश्वरम जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लागू करना भी टीआरएस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। सत्ताधारी टीआरएस पार्टी ने मिशन भागीरथ चलाकर घर–घर पीने का पानी मुहैया कराया। अपनी इस योजना से टीआरएस सरकार ने लोगा. का विश्वास जीता। विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना ने भी टीआरएस की जीत में मदद की है।

हालांकि जनता टीआरएस के कई मौजूदा विधायकों से नाराज़ थी, लेकिन केसीआर ने उन लोगों को इस चुनाव में दोबारा सीटें दे दी थीं। लेकिन जब पार्टी को जिताने की बात आई तो जनता ने टीआरएस के लिए खुले दिल से वोट किया। इन विधायकों के लिए लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा तो नहीं था कि पार्टी की हार का कारण बन जाए, लेकिन इससे पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार बहुमत का प्रतिशत कम हुआ है।

केसीआर को उनकी अच्छी छवि का फायदा भी मिला।

तेलंगाना आंदोलन के नेता रहे केसीआर का करिश्मा उन्हें लगातार दूसरी बार सत्ता में लाने पर कामयाब रहा। उनकी जीत की एक वजह ये भी रही कि उन्होंने 100 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में खुद जाकर रैलियां कीं। इससे वो चुनाव में पार्टी का चेहरा बनकर उभरे। टीआरएस ने उन इलाकों में भी जीत हासिल की, जहां आंध्र प्रदेश के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहां पार्टी उम्मीदवार ने कांग्रेस, टीडीपी, तेलंगाना जन समिति और सीपीआई के गठबंधन के उम्मीदवार को हरा दिया।

इन नतीजों ने ये साबित कर दिया कि टीआरएस ने तेलंगाना के आंध्र आबादी वाले इलाकों का विश्वास भी हासिल कर लिया है।

राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है कि लोगों को टीआरएस के सिंचाई, फंड और रोज़गार संबंधी वादों पर यक़ीन है। 2014 में हुए चुनाव के दौरान टीआरएस ने वादा किया था कि लोगों को दो कमरे का घर दिया जाएगा, बेरोज़गार लोगों के लिए एक लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और दलितों को कृषि के लिए तीन एकड़ की ज़मीन देने का वादा भी किया गया था। कहा जा रहा था कि लोग इन वादों के पूरा ना होने से नाराज़ हैं, जिसका मुक़सान टीआरएस को उठाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। टीआरएस का दोबारा सत्ता में आने का एक कारण विपक्ष में नेतृत्व की कमी भी है। कांग्रेस ने लंबे समय से अपनी प्रतिद्वंदी रही तेलुगुदेशम पार्टी के साथ गठबंधन कर जो दांव चला था, वो काम नहीं कर पाया और गठबंध का ये आइडिया नाकाम रहा। (साभार : बीबीसी)

खरी-खरी

असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तम्भ होती हैं !

"काम करने से आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो।"

सपा और बसपा ने बिना मांगे कांग्रेस को समर्थन क्यों दिया?

पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के उभार के साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस को लेकर सुर बदलने लगे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दो कदम पीछे क्या रही, सपा–बसपा ने तुरंत कांग्रेस को समर्थन की घोषणा कर दी, पहले बसपा ने तो फिर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रति नरमी दिखाई, जो यूपी की राजनीति में बदलाव का साफ संकेत हैं। कांग्रेस को समर्थन की घोषणा करने वाली ये वही बसपा है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि बसपा अब कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेगी। वहीं अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आते थे। अभी तक सपा व बसपा यूपी के गठबंधन में कांग्रेस को 4–5 सीट देने की ही बात किया करते थे, लेकिन परिस्थितियां अब बदल गई हैं। पांच राज्यों में कांग्रेस की जीत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सियासी कद बौना पड़ता दिख रहा है। लगातार हार के चलते जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था, इन नतीजों से उनका उत्साह बढ़ गया। साथ ही राहुल के नेतृत्व को भी मजबूती मिलना तय है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए पांच राज्यों के चुनाव परिणाम मोरल बूस्टर की तरह काम करेंगे।

धर, सपा और बसपा ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा के बाद उसे साइड लाइन करके गठबंधन तैयार कर लिया था और कांग्रेस को शामिल करने पर असमंजस व्यक्त कर रहे थे, अब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इन चुनाव नतीजों से सपा और बसपा को अब कांग्रेस को भी बराबर की अहमियत देनी पड़ेगी। यूपी में हाशिये पर पहुंच चुकी कांग्रेस को इन विधानसभा चुनाव के परिणामों से जहां संजीवनी मिलेगी, वहीं लोकसभा चुनाव में होने वाले सपा–बसपा गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उसकी बार्गेन पॉवर भी बढ़ेगी। सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात भी कर सकती है और उसकी जीत के आंकड़े में भी उछाल आ सकता है। इन चुनाव परिणामों ने यह भी देखने को मिला कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और दलित वर्ग कांग्रेस के साथ आया। यूपी के शहरी सीटों पर भी कांग्रेस की पकड़ रही है, जहां अल्पसंख्यक और दलित वोटर ज्यादा हैं ि ल ह ा ज ा कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो भी वह 2009 के आंकड़े को तो छू ही सकती है। तब कांग्रेस को 20 सीटें मिली थीं।

बहरहाल, सच्चाई यह भी है कि एक तरफ कांग्रेस खुश है तो वहीं उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता का स्वाद चख चुकी समा. जवादी पार्टी का पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिये कांग्रेस की जीत पर अखिलेश को इतराने और बीजेपी को आइना दिखाने से पहले स्वयं भी आईना देख लेना चाहिए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नोटा (इनमें से कोई नहीं) से भी कम वोट मिले। नोटा को जहां 0.5 प्रतिशत वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 0.2 प्रतिशत ही मत मिले। समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहा। बसपा छत्तीसगढ़ में 3.7 फीसदी, मध्य प्रदेश में 4.8 फीसदी और राजस्थान में चार फीसदी मतों के साथ कई सीटें हासिल करने में कामयाब रही। वहीं सपा को इन राज्यों में क्रमशः 0.2 फीसदी, 1.11 फीसदी और 0.2 फीसदी मतों से ही संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद से कांग्रेसियों ने यह संकेत देना भी शुरू कर दिया है कि यूपी में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पांच राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सपा–बसपा पर दबाव भी बढ़ाएगा और उन्हें अपने पुराने स्टैंड से वापस लौटने कें लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने भी कहा है कि वह यूपी के समान विच. ारधारा वाले को साथ लेकर चलने के पक्षधर हैं, लेकिन इसके लिये वह सम्मानजनक समझौते की बात भी करते हैं। बदली परिस्थिति में प्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन की भूमिका नए सिरे से लिखी जानी तय है।

कांग्रेस, बसपा और सपा से अलग बीजेपी की बात कि जाये तो पांच राज्यों के चुनाव नतीजे भाजपा के अनुकुल भले ही नही रहें हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन राज्यों में हुई चुनावी सभाओं की जीत का प्रतिशत 50 फीसदी से अधिक रहा। तेलंगाना जहां पहले भी भाजपा को कोई उम्मीद नहीं थी और छत्तीसगढ़ जहां नतीजे सभी पूर्वानुमानों के उलट आए, उनको अपवाद मान लें तो मप्र और राजस्थान में पहले की तरह योगी फैक्टर ने काम किया। (साभार : पीएस

हमेशा आराम की चाहत में, लोग आलसी हो जाते हो।

लगतार तीन बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं कमलनाथ

लंबे समय से लोकसभा के सदस्य है पहली बार वह 1980 में 7वीं लोकसभा से सांसद बने। उन्हें 1980 में इंदिरा गाँधी ने छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। इसके बाद वह लगातार 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सांसद रहे। 10वीं लोकसभा में वह भारत सरकार में जून 1991 में पर्यावरण एवं वन मंत्री बने। 1995–96 में वह केंद्रीय राज्य मंत्री, वस्त्र(स्वतंत्र प्रभार) बनाये गए। 12वीं और 13वीं 2004 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किये गए। 14वीं लोकसभा 2004–09 तक वह केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। 2009 में वह फिर से 15वीं लोकसभा में में निर्वाचित हुए और वह इस दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने। 2011 में उनका मंत्रालय बदल गया और उन्हें केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। कमलनाथ वर्तमान में 16वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है। साथ ही वह मध्यप्रदेश राज्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। 17 दिसंबर को कमलनाथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।(एजेंसी)

अशोक गहलोत के काम से काफी प्रभावित थीं इंदिरा गांधी

अशोक गहलोत (जन्म 3 मई 1951, जोधपुर राजस्थान) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता तथा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री बनेंगे। लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक डिग्री प्राप्त की तथा अर्थशास्त्र विषय लेकर स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। गहलोत का विवाह 27 नवम्बर, 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुआ। गहलोत के एक पुत्र वैभव गहलोत और एक पुत्री सोनिया गहलोत हैं। गहलोत को जादू तथा घूमना–फिरना पसन्द हैं। जानकारों का कहना है कि 'मारवाड़ का गांधी' माने जाने वाले गहलोत को राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर आई थीं। ऐसा कहा जाता है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में शरणार्थियों के बीच अच्छा काम कर रहे थे और इंदिरा उनके काम से काफी प्रभावित थीं। कुछ महीने पहले गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दमदार प्रदर्शन का श्रेय गहलोत को ही दिया जाता है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के महासचिव (संगठन) का पदभार संभाल रहे गहलोत को जमीनी नेता और अच्छा संगठनकर्ता माना जाता है। (एजेंसी)

सचिन पायलट ने क्षेत्रीय सेना में भी अपनी सेवा दी

सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर सन् 1977 को उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। नोयडा में वेदपुरा उनका पुश्तैनी गांव है। उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के जाने–माने नेता और केंद्रीय मंत्री थे। सचिन पायलट ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के एयर फ़ोर्स बाल भारती स्कूल से प्राप्त की तथा नई दिल्ली के ही सेंट स्टीफ़ेंस कॉलेज से स्नातक किया, तत्पश्चात उन्होंने अमेरिका के पेंसिलवेनिया विश्व. विद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। सचिन पायलट ने सन् 2004 में सारा अब्दुल्लाह से विवाह किया, जो कश्मीर के दिग्गज नेता फ़ारुक अब्दुल्ला की बेटी हैं। सचिन पायलट के दो बेटे हैं नाम आरान और वेहान पायलट। सचिन पायलट ने 10 फ़रवरी के दिन कांग्रेस से जुड़ने के साथ अपने राजनीतिक जीवन का पदार्पण किया। वे 14वीं लोकसभा में कांग्रेस की ओर दौसा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। इस समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी, जो भारत में सबसे कम आयु में सांसद बनने का कीर्तिमान भी था। इसके बाद 15वीं लोकसभा अर्थात 2009 के लोकसभा के चुनाव में वे अजमेर से सांसद चुने गए। सचिन पायलट ने क्षेत्रीय सेना में अपनी सेवा दी है, वे 6 सितंबर सन् 2012 को क्षेत्रीय सेना में सम्मिलित हुए। 21 जनवरी 2014 से उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष का पद भी संभाला है। (एजेंसी)

बेहद संकट के दौर में सौंपी गई थी भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की कमान

भूपेश बघेल का जन्म स्थान दुर्ग है जो कि पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और अब ये स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इनके पिता का नाम नंद कुमार और माता का नाम बिंदेश्वरी है जो कि किसानी किया करते थे। सन् 1961 को जन्में भूपेश की शादी मुक्तिश्वरी बघेल से हुई थी जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक नरेंद्र देव वर्मा की बेटी हैं। वहीं इस भूपेश बघेल के कुल चार बच्चे भी हैं। भूपेश बघेल ने राजनीति अपने गुरु चंदूलाल चंद्राकर से सीखी है और ये सन् 1985 में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) से जुड़ गए थे और कुछ समय बाद बघेल इसके मध्यप्रदेश कांग्रेस की युवा शाखा के उपाध्यक्ष भी बन गए थे। भूपेश बघेल ने अपना प्रथम चुनाव साल 1993 में मध्य प्रदेश असेंबली की पाटन सीट से लड़ा था। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये विधानसभा सीट मध्य प्रदेश राज्य की जगह छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आ गई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल को पार्टी की कमान बेहद संकट के दौर में सौंपी गई थी। सन 2013 का विधानसभा चुनाव बीत चुका था और पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था, राज्य में एक बार फिर रमन सिंह की सरकार पदारूढ़ हो चुकी थी।(एजेंसी)

किसी को सिर्फ अपने धर्म का सम्मान और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए।

भाजपा फाइनल भी इसी तरह खेली तो जाना तय

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावा. के जो परिणाम सामने आये हैं वह मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका हैं या राज्यों का नेतृत्व कर रहे भाजपाई मुख्यमंत्रियों के लिए, इसका विश्लेषण शुरू करने से पहले अगर गौर करें तो एक बात जो पूरी तरह साफ नजर आ रही है वह यह है कि इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सपने को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है। लोकसभा चुनावों से मात्र छह महीने पहले कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है उससे निश्चित ही पार्टी 2019 के लिए मजबूती के साथ उठ खड़ी होगी। वहीं भाजपा के लिए यह वाकई आत्म–अवलोकन का समय है क्योंकि चुनाव परिणाम जनता के बीच गहरी नाराजगी तो दर्शा ही रहे हैं।

इन चुनावों परिणामों ने एक बात और साफ कर दी है कि 2014 की तरह 2019 का लोकसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी रहेगा लेकिन 2014 के मोदी और राहुल में अब काफी फर्क आ चुका है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किये थे वह पूरे नहीं हुए हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति जो संशय 2014 में था वह अब धीरे–धीरे दूर होता जा रहा है। मोदी की छवि कट्टर हिन्दूवादी नेता की थी तो राहुल गांधी भी अब हिन्दूवादी नेता नहीं तो कर्मकाण्डी हिन्दू की अपनी छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जिस तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भाषणों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लग रहे घोटालों के आरोपों का जिक्र कर रहे थे अब उसी आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, और कहते हैं कि चौकीदार खुद चोर है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को नामदार और खुद को कामदार बताते हुए अपने चुनावी भाषणों के माध्यम से खूब तंज कसते रहे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ।

राहुल की जीत के दावों में कितना दम ? : अब राहुल गांधी ने दावा किया है कि जिस तरह 2018 के विधानसभा चुनाव जीते हैं उसी तरह 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन यहाँ राहुल गांधी को कांग्रेस की जीत के प्रति ज्यादा गर्वित इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें से तीन राज्यों में उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। भारतीय जनता पार्टी जोकि दो राज्यों– मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों से सत्ता में थी वहाँ वह सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही थी इसके अलावा तीसरे राज्य राजस्थान की परम्परा ही रही है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस को सरकार की कमान मिलती रही है। इन तीन राज्यों में ही कांग्रेस अपने प्रदर्शन पर गौर करे तो साफ नजर आ जायेगा कि मध्य प्रदेश में वह काँटे के मुकाबले में बस थोड़े से ही अंतर से आगे निकल पाई है। राजस्थान में भी वह भाजपा का सूपड़ा उस तरह नहीं साफ कर पाई है जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। पिछली बार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जहां 200 सदस्यीय विधानसभा में मात्र 21 सीटों पर सिमट गयी थी वहीं इस बार भाजपा 73 सीटों पर मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही।

छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है। इसी प्रकार यदि तेलंगाना में देखें तो तेलुगू देशम पार्टी के साथ गठबंधन करने की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी और वह दूसरे नंबर पर सिमट गयी। यह एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी रैली की थी। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो वहां से कांग्रेस साफ हो गयी है और इस राज्य के जाते ही देश का उत्तर–पूर्व भाग कांग्रेस मुक्त हो गया है। इस तरह कांग्रेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे सिर्फ उन्हीं राज्यों में जीत मिली है जहां वह भाजपा के साथ सीधे टक्कर में है और सरकार के खिलाफ नाराजगी का फायदा ही उसे मिल पाया है। फिर भी, परिणामों पर कांग्रेस को खुशी तो जतानी चाहिए लेकिन पार्टी को भाजपा को हल्के में लेने की को. शिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवा पार्टी ने उसे काँटे की टक्कर दी है।

मोदी लहर का अब नामोनिशां नहीं : भाजपा जब भी अपनी इस हार की समीक्षा करेगी तब उसे इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्यों उसके अधिकांश नेताओं, प्रवक्ताओं, मंत्रियों आदि में अहंकार आ गया है और वह आम जन से कटते जा रहे हैं और खुद को ही सबसे बुद्धिमान समझते हैं। भाजपा को तीन बड़े राज्य खोने के साथ ही जो एक और बड़ा नुकसान हुआ है वह है इसके क्षेत्रीय क्षत्रपों का प्रभुत्व खत्म होना।

शिवराज सिंह चौहान, डॉ. रमन सिंह और वसुंधरा राजे भाजपा के प्रमुख स्तम्भों में से थे और यदि यह फिर से सत्ता में आ जाते तो आगे चलकर पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन सकते थे लेकिन अब ऐसा शायद ही हो पाये। इन तीनों बड़े नेताओं को अब अपनी जमीन फिर मजबूत करने में ही काफी समय लग सकता है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा का जो विजय रथ निकला था उसने धीरे–धीरे एक एक करके कई राज्यों पर कब्जा जमाया।(साभार : पीएस)

जीवन के आचरण में न्याय तभी संभव है जब यह सबसे पहले नागरिकों के दिलों और आत्मा में मौजूद हो।

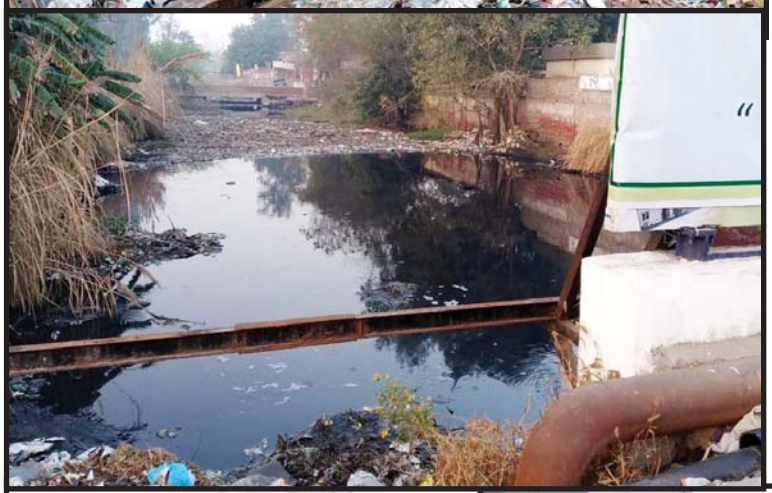

रासायनिक कचरे के बीच फंसा जीडीए का पॉश एरिया वैशाली

गाजियाबाद में वैशाली जो दिल्ली से सटा हुआ है और साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में होने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है साथ में तीन तरफ से गंदा नाला है जिस में रासायनिक कचरा भारी मात्रा में डाला जाता है साथ में साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति और सरकारी धन की लूट होती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी मालामाल हो रहे जांच के नाम पर बिसलेरी का पानी डाल कर के सैंपल को पास कर दिया जा रहा है नाले की स्थिति को बयान करती हुई मैं कुछ फोटोग्राफ आपके प्रेषित कर रहा हूं जो स्वयं इस क्षेत्र की हकीकत बयान करने वाली है स्वच्छ भारत अभियान विज्ञापन की तो लूट हो रही है। नाला इतना गंदा है उसमें पेड़–पौधे जमे हुए हैं वर्षों तक उसमें साफ सफाई नहीं हुई है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गरीब जनता को मरने के लिए शासन–प्रशासन मजबूर कर रहा है यहां पर लोगों को स्वास की बीमारी एवं फेफड़े में जलन की शिकायतें आए दिन होती जा रही हैं। यहां हॉस्पिटल ने अपना जाल बिछा दिया है चारों तरफ लूट मची हुई है।

ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए जब हम अन्याय का विरोध करने में असफल हो जाएं।

रेरा कानून कैसे यह रियल एस्टेट इंडस्ट्री और घर खरीददारों को करेगा प्रभावित

रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और घर खरीददारों के हितों की रक्षा करने के मकसद से रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट), 2016 (RERA) को लागू किया गया। भारत सरकार ने 26 मार्च 2016 को रियल एस्टेट (रेगुलेशन और डिवेलपमेंट) एक्टर 2016 अधिनियमित किया और इसके सभी प्रावधान 1 मई, 2017 से लागू हो गए। सभी बिल्डर्स से कहा गया कि वे जुलाई 2017 तक अपने प्रोजेक्ट्स को RERA के तहत रजिस्टर कराएं। जो रियल एस्टेट एजेंट्स इसके दायरे में आते हैं, वे अब भी खुद को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कई राज्यों को अब भी इस कानून के नियमों को नोटिफाई करना है और डिवेलपर्स/प्रमोटरों को अपने प्रोजेक्ट्स को RERA में रजिस्टर्ड कराना है।

क्या है RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट)

रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद घर ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को पास कर दिया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरक. ारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।

क्यों जरुरी है RERA?

काफी वक्त से घर खरीददार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि रियल एस्टेट की लेनदेन एकतरफा और ज्यादातर डिवेलपर्स के हक में थीं। RERA और सरकार के मॉडल कोड का मकसद मुख्य बाजार में विक्रेता और संपत्ति के खरीददार के बीच न्यायसंगत और सही लेनदेन तय करना है। उम्मीद की जा रही है कि RERA बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर रियल एस्टेट की खरीद को आसान बनाएगा। साथ ही राज्यों के प्रावधान केंद्रीय कानून की भावना को कमजोर नहीं करेंगे। RERA भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहला रेगुलेटर है। रियल एस्टेट एक्ट के तहत यह अनिवार्य किया गया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने रेगुलेटर और नियमों का गठन करेंगे, जिसके मुताबिक कामकाज होगा।

घर खरीददारों पर क्या होगा RERA का प्रभाव

कुछ अहम अनुपालन हैं:

- कोई भी अतिरिक्त इजाफा या परिवर्तन के बारे में आवंटियों को सूचना देना।
- किसी भी इजाफे या बदलाव के बारे में 2/3 आवंटियों की मंजूरी की जरूरत होगी।
- RERA में रजिस्ट्रेशन से पहले किसी तरह का लॉन्च या विज्ञापन नहीं किया जाएगा।
- अगर बहुमत अधिकार तीसरे पक्ष को ट्रांसफर किया जाना है तो 2/3 सहमति की जरूरत होगी।
- प्रोजेक्ट प्लान, लेआउट, सरकारी मंजूरी और लैंड टाइटल स्टेटस और उप–ठेकेदारों की जानकारी साझा करना।
- वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा होकर ग्राहकों को मिल जाए, इस पर जोर दिया जाएगा।
- पांच साल की दोष दायित्व अवधि के कारण कंस्ट्रक्शन की क्वॉलिटी में इजाफा।
- ब्योरेवार समय या काफी फ्लैट्स बिक जाने के बाद आरडबल्यूए का गठन।

इस कानून का सबसे सकारात्मक पहलू है कि यह फ्लैटों, अपार्टमेंट आदि की खरीद के लिए एक एकीकृत कानूनी व्यवस्था मुहैया कराता है, साथ ही पूरे देश में उसका मानक. ीकरण करता है। अब आपको इस कानून की मुख्य बातों के बारे में बताते हैं:

रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना: रियल एस्टेट के लिए सही रेगुलेटर (जैसे कैपिटल मार्केट के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) की जरूरत लंबे वक्त से थी। इस कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसका मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा, जमा किए डाटा को संग्रहित करना और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाना है। समय की बर्बादी को रोकने के लिए प्राधिकरण को अधिकतम 60 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है। यह सीमा तभी बढ़ाई जा सकती है, अगर देरी का कोई कारण दर्ज हो। इसके अलावा रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण (त्न।ज) में अपील की जा सकती है।

अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: केंद्रीय कानून के मुताबिक सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स (जहां विकसित होने वाला कुल क्षेत्रफल 500 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा है या किसी भी चरण में 8 से ज्यादा अपार्टमेंट्स बनने अनिवार्य हैं) का अपने राज्य के RERAमें रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जिन मौजूदा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) या ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त प्रोमोटर्स को प्रोजेक्ट की जानकारी जैसे–जमीन की स्थिति, प्रोमोटर की जानकारी, अप्रूवल, पूरे होने का समय इत्यादि बतानी होगी। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी मंजूरियां मिल जाएंगी, तब प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जा सकती है।

रिजर्व अकाउंट: प्रोजेक्ट्स में देरी होने की सबसे मुख्य वजह है कि एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा कर उसे दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रोमोटर्स को प्रोजेक्ट का 70 प्रतिशत पैसा अलग रिजर्व अकाउंट में रखना होगा। इस खाते की राशि को सिर्फ जमीन या निर्माण के कामों में खर्च किया जा सकता है। किसी पेश. ेवर से इसे सर्टिफाइड कराना भी जरूरी है।

प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख सकेंगे ग्राहक: RERA के लागू होने के बाद घर खरीददार RERA की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मालूम कर सकेंगे। प्रोजेक्ट में कितना काम पूरा हुआ, इसकी जानकारी प्रोमोटर्स को नियमित अंतराल पर नियामक को देनी होगी।

टाइटल रिप्रेजेंटेशन: प्रोमोटर्स को अब सही टाइटल और जमीन पर रुचि के लिए सकारात्मक वॉरंटी बनानी होगी, जिसे बाद में घर खरीददार उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत टाइटल की खोज की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें टाइटल और प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्श्योरेंस भी हासिल करनी होगी, जिसका मुनाफा बिक्री समझौते के निष्पादन के बाद अलॉटी को दिया जाना चाहिए।

बिक्री समझौते का मानकीकरण: इस कानून के तहत प्रोमोटर्स और घर खरीददार के

आजादी दी नहीं जाती, हासिल करनी पड़ती है।

बीच बिक्री समझौते का मानक मॉडल है। मिसाल के तौर पर प्रोमोटर्स ने घर खरीददारों के लिए कई धाराएं डालीं, जो उनके लिए सजा जैसी थीं, लेकिन प्रमोटर्स अगर कोई गलती करते थे तो उन पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती थी। लेकिन ऐसे क्लॉज अब बीते दिनों की बात हो जाएंगे और घर ग्राहकों को भविष्य में एक संतुलित अग्रीमेंट मिलेगा।

पेनाल्टीः इस कानून का उल्लंघन न हो, इसके लिए सख्त जुर्माने (प्रोजेक्ट की लागत का 10 प्रतिशत) का प्रावधान है।

RERA के तहत कारपेट एरिया की परिभाषाः

प्रॉपर्टी का एरिया तीन तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है–कारपेट एरिया, बिल्ड–अप एरिया और सुपर बिल्ड–अप एरिया। इसलिए जब भी बात प्रॉपर्टी खरीदने की आती है तो आप क्या चुकाएंगे और आपक. ो क्या मिलेगा, इसके बीच काफी फर्क होता है। महाराष्ट्र RERA के चेयरमैन गौतम चटर्जी ने कहा, अब यह सभी बिल्डर्स के लिए अनिवार्य है कि वे अपार्टमेंट का साइज कारपेट एरिया (चार दीवारों के बीच का एरिया) के आधार पर बताएं। इस्तेमाल होने वाले इल एरिया में टॉयलेट एवं किचन भी शामिल होंगे। इससे पारदर्शिता आएगी, जो पहले नहीं थी।

RERA के मुताबिक कारपेट एरिया किसी अपार्टमेंट का इस्तेमाल होने वाला एरिया होता है, जिसमें बाहरी दीवारों का एरिया, सर्विस शाफ्ट, बालकनी और वरांडा एरिया शामिल नहीं होते। फ्लैट के अंदर की दीवारों का एरिया इसका हिस्सा होता है।

सुमेर ग्रुप के सीईओ राहुल शाह ने कहा, RERA की गाइडलाइंस के मुताबिक, बिल्डर को सटीक कारपेट एरिया की जानकारी देनी होगी, ताकि ग्राहकों को यह पता चल सके कि वह किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। लेकिन कानून के तहत बिल्डरों को कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना अनिवार्य नहीं है।

RERA के तहत कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगेः

- प्लॉटेड डिवेलपमेंट के अलावा कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स
- 500 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा या 8 यूनिट्स वाले प्रोजेक्ट्स।
- कानून के लागू होने से पहले बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले प्रोजेक्ट्स।
- जिस प्रोजेक्ट का मकसद रेनोवेशन, रिपेयर, री–डिवेलपमेंट है और पुनः आवंटन, मार्केटिंग, विज्ञापन, नए अपार्टमेंट्स की बिक्री या नया आवंटन नहीं करना है, वह RERA के तहत नहीं आएंगे।
- हर चरण को नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट माना जाएगा, जिसके लिए नया रजिस्ट्रेशन होगा।

किन चीजों पर बिल्डर को माननी होगी RERA की बातः

- प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन
- विज्ञापन
- निकासी दृ पीओसी विधि
- कारपेट एरिया
- वेबसाइट अपडेशन/भंडाफोड़
- प्रोजेक्ट में बदलाव–2/3 अलॉटीज की मंजूरी
- प्रोजेक्ट अकाउंट्स–ऑडिट
- अलॉटी से लिया गया 70 प्रतिशत फंड प्रोजेक्ट के अकाउंट में जमा कराना होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ निर्माण और जमीन की लागत को कवर करने के लिए होगा।
- पर्सेंटेज कंप्लीशन मेथड के अनुपात में निकासी होगी।
- निकासी किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट या सीए द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए।
- गैर–अनुपालन पर प्रोजेक्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के RERA के प्रावधान।
- देरी पर ब्याज कंज्यूमर और प्रोमोटर दोनों के लिए एक समान होगा।

RERA के तहत बिल्डर को क्या–क्या जानकारियां देनी होंगीः

- नंबर, टाइप और अपार्टमेंट का कारपेट एरिया।
- किसी भी बड़े इजाफे या बदलाव के लिए प्रभावित आवंटियों से सहमति।
- ना बिक पाने वाली इन्वेंट्री या लंबित मंजूरियों जैसी जानकारियों को हर तिमाही में RERA की वेबसाइट पर अपडेट करना।
- तय वक्त में प्रोजेक्ट पूरा करना।
- विज्ञापन में झूठे बयान या कमिटमेंट नहीं करना।
- प्रोमोटर मनमाने ढंग से यूनिट को रद्द नहीं कर सकता।

RERA के तहत कैसे रजिस्टर कराएं प्रोजेक्ट्सः

- RERA के तहत प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त सभी मंजूरियों का प्रमाणपत्र, प्रारंभिक प्रमाणपत्र, मंजूर किया गया प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशन, विकास कार्य का प्लान, प्रस्तावित सुविधाएं, अलॉटमेंट लेटर, सेल अग्रीमेंट और कन्वेयंस डीड पेश करने पड़ते हैं।
- नए और मौजूदा प्रोजेक्ट्स का लॉन्च से पहले RERA के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- RERA और RERA अपीलीय ट्रिब्यूनल में विवाद का 6 महीने में निपटारा।
- एक ही प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों का अलग–अलग रजिस्ट्रेशन होगा।
- डिवेलपर्स को RERA को पिछले 5 वर्षों में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट का उनके स्टेटस के साथ ब्योरा देना होगा। साथ ही बताना होगा कि देरी क्यों हुई।
- RERA की वेबसाइट पर अपडेट।
- अगर डिवेलपर की गलती नहीं है और देरी हुई है तो अधिकतम 1 साल का एक्सटेंशन लिया जा सकता है।
- सीए द्वारा प्रोजेक्ट के अकाउंट का सालाना ऑडिट।
- आरडब्ल्यूए के फेवर में कॉमन एरिया का कन्वेयंस डीड।
- निर्माण और लैंड टाइटल का इंश्योरेंस।
- प्रोजेक्ट के पूरा होने की समयावधि।

RERA में शिकायतः

आरआईसीएस के पॉलिसी हेड दिग्बिजॉय भौमिक ने कहा, रियल एस्टेट रेग्युलेशन एक्ट 2016 के सेक्शन 31 के तहत रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी या निर्णायक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऐसी शिकायतें प्रमोटरों, आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ हो सकती हैं। ज्यादातर राज्यों के नियमों में RERA को अपरिवर्तनीय बनाया गया है, जिसमें फॉर्म और प्रक्रिया है। इसके तहत आवेदन किया जा सकता है। चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश या उत्तर प्रदेश के मामले में इन्हें फॉर्म एम या फॉर्म एन कहा गया है। (ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में भी ऐसा ही है) राज्यों के RERA के तहत शिकायतें तय फॉर्म के रूप में होनी चाहिए। RERA के तहत पंजीकृत प्रोजेक्ट अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो तय समय सीमा के भीतर उनके खिलाफ इस कानून के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। एसएनजी एंड पार्टनर्स लॉ फर्म में पार्टनर अजय मोंगा ने कहा, "जिन लोगों ने एनसीडीआरसी में शिकायतें दर्ज कराई हैं, वह उन्हें वापस लेकर RERA में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अन्य अपराध (धारा 12, 14, 18 और 19 के तहत शिकायतें छोड़कर) RERA प्राधिकरण के सामने दायर की जा सकती हैं"।

अधिक जानकारी के संपर्क करें
संतोष मिश्रा 9560522777

नौकरशाह के लिए दुनिया महज एक हेर–फेर करने की वस्तु है .

CONSULT and LEARN

(Also online)

Astrology, Palmistry & Vaastu

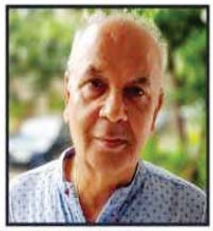

with Senior Jyotish Acharya

S.K. Sharma

27+ Yrs. Exp., Award Winner

CONSULTATIONS : On any issues of your life along with Vedic Astro, Gems, Vaastu and Vedic Mantras Guidelines for Self Chatting the Mantras to get good results against problems, Vaastu visits for Vaastu Corrections to remove Vaastu doshas without any demolitions of structure

TEACHING: Astrology, Palmistry, Numerology, Vaastu and Fengshui in short durations of time from root level to expert level. Please visit following website for more details www.astropalmistvaastuguru.com

Indirapuram : T-12 (Third floor), Module-9, Mangalam Residency, Abhay Khand-3, Indirapuram, Gzb.

Gurgaon : Flat No. 1, Tower 2, Vipulgreen Society, Sohna Road, Sec-48

Mob. No.: 9818952437, 8745824922

E-mail: astrogurusks@gmail.com, Web.: www.astropalmistvaastuguru.com

Please visit "YOU TUBE", type Astrologer S.K. Sharma for More Details

गौ रक्षा हेल्पलाइन परिवार का संकल्प

कामधेनु पंचगव्य क्रान्ति के माध्यम से घर-घर गऊ उत्पाद पहुंचाना है

Alok Solanki
Chairman
+91-9990927493

अगर सरकार को बीफ एक्सपोर्ट से इन्कम नजर आती है तो गऊ उत्पाद से हजारों करोड़ का लाभ सरकार को नजर क्यों नहीं आता, क्या आप इस संकल्प में हमारे साथ हैं?

KAMDHENU

International Panchgavya Research & Marketing Pvt. Ltd.

A Unit of gramin Vikas And Gau Sewa Sansthan

✦ Cosmetics ✦ Dairy ✦ Medicines

✣ Desi Ghee ✣ Dhoop Batti ✣ Gau Nyle ✣ Shampoo ✣ Soaps ✣ Toothpaste ✣ Gobar Ke Ganpati ✣ Gobar Ki Tiles ✣ Gobar Ke Kande ✣ Organic-Haldi ✣ besan ✣ Honey

गौ रक्षा हेल्पलाइन से जुड़ने हेतु सम्पर्क करें : 8800130057 www.cowhelpline.com

011-65656528, 8800130057

गौ-रक्षा हेल्पलाइन : 011-6565-6464, पंचगव्य हेल्प लाइन नं. : 9999092304

EDUCATION SOLUTION

Education Solution

One Door Solution For All Educational Needs

Save Your Years and Regularise Your Studies with "NIOS" Board Home Tuition Assignments Are Also Provided at Affordable Cost

Complete Your Syllabus in Summer Vacation

Now in Indirapuram Niti Khand -1

Abacus Classes Also Available

ACADEMIC COACHING

Ist - VIIIth	IXth - Xth	XIth - XIIth	B.Com, B.A-B.Sc
MATHS SCIENCE, ENGLISH HINDI, S.ST.	MATHS SCIENCE, ENGLISH HINDI, S.ST.	MATHS, PHYSICS, CHEMISTRY BIOLOGY ENGLISH, ACCOUNTS ECONOMICS B.st, C++, I.P.	ACCOUNT, ECONOMICS MATHS INCOME TAX CORP. ACCOUNTING BUSINESS LAW COST ACCOUNTING

PROFESSIONAL COACHING

CA-CPT,CS,ICWA	BBA, MBA	B.Tech, MBBS
CA-CPT, IPCC CS (Foundation) CS (Executive) CMA (Foundation) CMA (Inter Mediate)	INCOME TAX, COSTING FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATE ACCOUNTING FINANCIAL ACCOUNTING BUSINESS LAW	IIT-JEE, BITSAT CPMT, UPTECH **Competitive Exam** POLYTECHNIC BANK ENTRANCE, UPSE SSC, SPOKEN ENGLISH, ETC.

HEAD OFFICE : PLOT NO 420 SECTOR 5 VAISHALI GHAZIABAD, BEHIND SHOPRIX MALL

Office : 0120-4130999 | M. : 9911932244, 9999232199, 9999207099, 9999907099

Email: educationsolutionvep@gmail.com | www.educationsolution.co

Suresh Pandey 9810514888

INDIAN/FOREIGN BOOKS, JOURNALS

NEW/OLD LAW BOOKS

BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIES

SK

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4 West Vinod Nagar, Delhi-110092

mail- suresh66pandey@gmail.com, pandeysureshk@gmail.com
Web:-www.skacademic.com

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।
- लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना।
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना।
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।
- धार्मिक जागरुकता फैलाना।

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
मोबाइल : 9810960818 ई मेल : lokjagriti@gmail.com

RNI NO.UPHIN/2011/39809

LEGEAZY
INTERNATIONAL
FREEDOM OF LIFE

Legeazy membership is a unique concept which provides consultancy without any hassle, Free of cost and with trusted qualified professionals

* Personal legal assistance
* Commercial & consumer dispute
* Corporate matters Income Tax and service tax mattters.
* Regd. of Company, Service Tax, Trust, society trade mark etc.
* Property documentation, Validation, title investigation and Advise.
* Criminal and civil matters.
* Builders buyers disputes.
* Family disputes and consultancy on marital discords.
* Accounting/Book Keeping.
* Claims and Settlement.

Off. Add:- 3A/95, Vaishali Ghaziabad, U.P. 201010
Mob. No.:-9560522777, 9810960818
Email: info@legeazy.com Website : www.legeazy.com